DD
RNI No. DLHIN/25/A2321
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र
दिव्य दिल्ली
वर्षः 01, अंकः 31, पृष्ठः 08
infodivyadelhi@gmail.com
शनिवार, 11 अक्टूबर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री | सूर्योदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा एसआईआर

राजेश चौहान
नई दिल्ली
चुनाव आयोग देश में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू कर सकता है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत उन राज्यों से हो सकती है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची संशोधन अभियान नहीं चलाएगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं या हो रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव मशीनरी, निकाय चुनाव में व्यस्त है और इसके चलते वे एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे।

इन राज्यों में शुरू हो सकती है एसआईआर की प्रक्रिया
गौरतलब है कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांच राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी रक्फ़ की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण शुरू करने का काम चल रहा है और इसे शुरू करने पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश
अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस महीने की शुरूआत में एक सम्मेलन में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) से अगले 10 से 15 दिनों में एसआईआर शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा था।

एसआईआर देश में लागू हुआ तो हमारे पास होने चाहिए कौन से दस्तावेज

मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैः
जन्म तिथि/आयु का प्रमाण- (इनमें से कोई एक)
- जन्म प्रमाण पत्र
- भारतीय पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- कक्षा 10वीं या 12वीं का अंकपत्र/प्रमाण पत्र (यदि उसमें जन्मतिथि दी गई हो)

निवास स्थान का प्रमाणः (इनमें से कोई एक, जो आपके पते को प्रमाणित करे)
- बैंक/डाकघर की चालू पासबुक
- राशन कार्ड
- नवीनतम रेंट एग्रीमेंट
- पानी/बिजली/गैस/टेलीफोन का नवीनतम बिल

अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित रखें

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित रखें। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची की अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच थी। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य अवैध मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर निकालना है।

क्या विचाराधीन कैदियों को भी मतदान का हक? मांग जवाब

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों के मताधिकार को फिर मान्यता देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की इस दलील पर गौर किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत लगाया गया वर्तमान पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

भारत-अफगानिस्तान के बीच मजबूत होंगे हवाई संपर्कः मुत्ताकी

नई दिल्ली
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि वह भारत की राजधानी दिल्ली में आकर बेहद खुश हैं। यह उनका भारत का पहला दौरा है बतौर विदेश मंत्री। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारत सरकार की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया। मुत्ताकी ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल थे।

'हवाई संपर्क को मजबूत करने पर बनी सहमति'
उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ने काबुल में अपने दूतावास की तकनीकी उपस्थिति को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही, जल्द ही इस्लामिक अमीरात (अफगानिस्तान) का राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली पहुंचेगा।' दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हवाई संपर्क (एयर कॉरिडोर) को भी मजबूत करने पर सहमति बनी है। मुत्ताकी ने बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का भरोसा दिया है। उन्होंने हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों को भारत की ओर से दी गई मदद के लिए भी आभार जताया। इसके अलावा, भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर एक 'व्यापार समिति' बनाने का भी निर्णय लिया है। मुत्ताकी ने बताया कि अफगानिस्तान में निवेश के लिए नए अवसर खुले हैं, खासकर खनिज और ऊर्जा के क्षेत्र में।

सावलकोट परियोजना को केंद्र की मंजूरी, पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

नई दिल्ली
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लगा दिया। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए चिनाब नदी के पानी पर रोक लगा दी। ऐसे में अब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी कर ली। सिंधु जल संधि के निलंबन के बीच केंद्र ने चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को मंजूरी दी है। जिससे साफ होता है कि भारत का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि पानी को लेकर पुरानी रियायतों का दौरा खत्म हो चुका है।

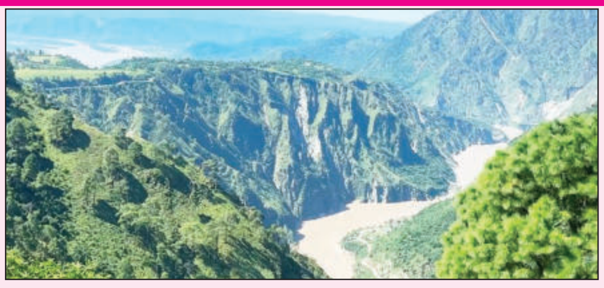

1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण परियोजना पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद फिर से जीवित की जा रही है। लगभग चार दशकों से रुकी हुई, सावलकोट परियोजना चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदी जल के अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने का काम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र की ओर से संधि को निलंबित करने की घोषणा के कुछ महीने बाद हुआ।

केरल हाईकोर्ट का एसआईटी को आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश

कोच्चि
प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला मंदिर में स्वर्ण-पल्लवन (सोने की परत) की कथित चोरी के मामले में केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (10 अक्तूबर) को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर के 'द्वारपालक' मूर्तियों से सोना चोरी के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने यह आदेश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखा उत्पादन और बिक्री का मामला, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने शीर्ष अदालत से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी। दलीलों में कहा गया कि पटाखों के इस्तेमाल के समय को लेकर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगी
सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगते हुए दिल्ली-एनसीआर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (ठएएफ्क्र) समय-समय पर पटाखों के उत्पादन कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में केवल स्वीकृत ग्रीन फायर फॉर्मूलेशन ही बेचे जाएं। निर्माताओं को ग्रीन पटाखों की मात्रा और विवरण बताना होगा। सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत को यह सुझाव भी दिया गया कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करना चाहिए।

अंतरिक्ष में अब राष्ट्रीयता का नहीं, मानवता का सवाल है

जब कोई अंतरिक्ष में जाने के लिए धरती छोड़ता है, तो पृथ्वी उसकी पहचान बन जाती हैः शुभांशु शुक्ला

नई दिल्ली
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष में जाने के लिए धरती छोड़ता है, तो पृथ्वी उसकी पहचान बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में अब राष्ट्रीयता का नहीं, बल्कि मानवता का सवाल है। शुभांशु शुक्ला ने यह बात छात्रों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही।

स्पेस स्टेशन के अनुभव किए साझा
दरअसल, शुभांशु शुक्ला भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से संबद्ध स्कूलों के छात्रों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। गोवा में मौजूद शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है।

अंतरिक्ष स्टेशन में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन से बाहर देखने पर ऐसा लगा जैसे किसी ऐसे दफ्तर में हों, जहां से सबसे अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा हो। शुभांशु शुक्ला ने "प्रज्वलित मन, सीमाओं की खोज करनाः अंतरिक्ष, शिक्षा और उद्योग का अभिसरण" शीर्षक वाले सत्र में हिस्सा लिया, जहां स्पेस स्टेशन को लेकर बताया कि यह बहुत ही आकर्षक था। संवाद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि इस दुनिया में लोगों की अलग-अलग पहचान हो सकती है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष में होता है तो वे धुंधली हो जाती हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि, "जब आप बच्चे होते हैं और स्कूल जाते हैं, तो हमारा घर और माता-पिता हमारी पहचान बन जाते हैं। जब हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज हमारी पहचान बन जाता है। जब आप शहर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो वह शहर आपकी पहचान बन जाता है। जब आप विदेश जाते हैं, तो आपका देश आपकी पहचान बन जाता है।"

टीवीके की याचिका पर 'सुप्रीम' फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके और अन्य द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पक्षकार, पीड़ितों, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं। सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले पीड़ितों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर करे।

घटना का सीबीआई जांच की मांग
इससे पहले मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की सीबीआई जांच से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु के भाजपा नेता जी एस मणि ने भी भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। टीवीके ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है।

30 दिन में 'लाल आतंक' को चोटः 26 नक्सली खत्म तो 98 ने डाले हथियार

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 'सीआरपीएफ' और इसकी विशेष इकाई 'कोबरा', डीआरजी व राज्यों की पुलिस, नक्सलियों के खात्मे/सरेंडर कराने में लगी हैं। सितंबर माह के दौरान सुरक्षा बलों को इस मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ एवं संबंधित राज्यों की पुलिस के समक्ष 98 माओवादियों ने सरेंडर किया है। साथ ही 98 माओवादी पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए हैं। सीआरपीएफ/कोबरा, ने नक्सलियों के गढ़ में लगातार बढ़त लेते हुए छत्तीसगढ़ में 100 एफओबी स्थापित कर लिए हैं। सीआरपीएफ की सक्रियता भूमिका वाले क्षेत्रों में सितंबर माह के दौरान 64 हथियार भी बरामद किए हैं। विभिन्न इलाकों में 55 आईईडी, 2656 राउंड गोलियां, 94 ग्रेनेड, दो बम, 1006 डेटोनेटर, 113.85 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ,

177140 रुपये कैश, 45 जिलेटिन स्टिक और 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर सीआरपीएफ व दूसरे बलों के जवान 48 घंटे में 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस' स्थापित कर रहे हैं। अब इसी एफओबी के चक्रव्यूह में फंसकर नक्सली मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ऐसा जाल बिछाया है कि जिसमें नक्सलियों के पास दो ही विकल्प बचते हैं। एक, वे सरेंडर कर दें और दूसरा, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गोली खाने के लिए तैयार रहें। केंद्रीय सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नक्सलियों का अंत अब कितना निकट है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में 50 नक्सली मारे गए थे तो वहीं 2024 में मुठभेड़ के दौरान 290 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। 2025 में करोड़ों रुपये के दर्जनभर इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं। 2019 से लेकर अभी तक घने जंगलों में साढ़े तीन सौ से ज्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं। 2024 में 58 कैंप स्थापित हुए थे। इस वर्ष सीआरपीएफ ने अकेले छत्तीसगढ़ में ही 100 कैंप स्थापित कर दिए हैं। ये एफओबी नक्सलियों के किले को ढहाने में आखिरी किल साबित हो रहे हैं। जिस तेजी से 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस' स्थापित हो रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की लगातार उठ रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है ताकि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने से जुड़ी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल कर सके। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित ये याचिकाएं शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक सहित कई लोगों ने दाखिल की हैं। इन

याचिकाओं में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वादे के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द फिर से राज्य का दर्जा दे।
वहीं मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें अनुच्छेद 370 को रद्द करने को सही ठहराया गया था और केंद्र को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 तक कराने और जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जा सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने पहले यह निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सेप्टंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं।

वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम
दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस आशय की घोषणा शुक्रवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल समिति ने की।वेनेजुएला की पूर्व सांसद 56 वर्षीय मचाडो को देश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से न्यायपूर्ण तथा शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। आगामी 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (लगभग 96 करोड़ रुपये) और प्रशस्ति पत्र मिलेगा।

तमिलनाडु में दवाओं की टेस्टिंग में मिली थी भारी कमी: कैग

नई दिल्ली
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की जान गई है। इस मामले ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में इस दवा पर बैन लगा दिया दया है। इन सब के बीच दवाओं की टेस्टिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पिछले साल की तमिलनाडु में दवा टेस्टिंग में भारी कमी की ओर इशारा किया था। अब कोल्ड्रिफ कफ सीरप से हुई नौनिहालों की मौत के बाद इस खुलासे ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सामने आई कैग की रिपोर्ट में औषधि निरीक्षण और नमूने उठाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियों को दर्शाया था। ये रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 को सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 में तमिलनाडु में 1,00,800 जांच का लक्ष्य रखा गया था; हालांकि, केवल 66,331 निरीक्षण ही किए जा सके थे। जिसका सीधा मतलब है कि टारगेट से 34 प्रतिशत कम जांच हो पाई थी। वहीं, करीब तीन साल बाद 2020-21 में दवाइयों की जांच के लिए जो टारगेट रखा गया उसमें 38 प्रतिशत की कमी देखने को मिली थी। इस अवधि के दौरान, 1,00,800 निरीक्षण किए जाने थे, लेकिन केवल 62,358 निरीक्षण ही किए गए। हैरान करने वाली बात है कि 2019-20 के दौरान सबसे ज्यादा 40% की कमी दर्ज की गई। वहीं, 2020-21 में यह कमी 54% दर्ज की गई।

औषधि निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया
बता दें कि दवाओं जहां बनती हैं, उस दौरान इस इसकी टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट को रोकना है। बता दें कि ये जांच औषधि निरीक्षकों द्वारा की जाती है। वहीं, उनकी मंजूरी के बाद ही खुदरा दुकानों और क्लीनिकों तक दवाएं पहुंचती हैं।

देश का विभाजन धर्म के नाम पर करना बहुत बड़ी गलती : शाह

'जितना इस मिट्टी पर हमारा अधिकार, उतना ही बांग्लादेश-पाकिस्तान से आए हिंदुओं का: अमित शाह

नई दिल्ली
लेखक नरेन्द्र मोहन की जयंती के अवसर पर 10 अक्टूबर, 2025 को उनकी स्मृति में जागरण साहित्य सृजन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चयनित लेखक को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने कहा कि आपातकाल के समय नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
गृहमंत्री ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर करना बहुत बड़ी गलती थी; आपने भारत माता की भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल बना दिया। मैं देश के सभी नागरिकों से पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला देश के नागरिकों के अलावा किसी और को करने का अधिकार होना चाहिए क्या? भाजपा ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र को 1950 के दशक से स्वीकार किया है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट भी करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट भी करेंगे, और इस देश से डिपोर्ट भी करेंगे।

कुछ पार्टियों ने वोटबैंक देखना शुरू कर दिया : अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि असम में 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी। यह घुसपैठ के बिना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40% है, और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% तक पहुँच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि घुसपैठ अतीत में हुई है। घुसपैठ में कुछ पार्टियों ने वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्होंने घुसपैठियों को प्रश्रय दिया है। हमारे गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी है, लेकिन वहाँ घुसपैठ नहीं होती।

भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी : अमित शाह

भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई।

'पत्रकारों पर कोई बंधन नहीं रखा'
अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोहन जी जब भाजपा की टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने, तब उनसे पत्रकारिता की इंटिग्रिटी पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मेरे पास केवल एडिटोरियल है, बाकी सारा पेज आपके पास है। आपको जो लिखना है, लिखें। उन्होंने कभी भी पत्रकारों पर कोई बंधन नहीं रखा था। अमित शाह ने कहा कि जब आपातकाल लगा, तब हमारे देश के लोकतंत्र की और पत्रकारिता की परीक्षा थी। नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में खिलाफ लड़ाई लड़ी।

बांग्लादेश में हिंदू 22% थे, अब मात्र 7.9% रह गए: शाह

अब वहाँ हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक केवल 1.73% रह गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू 22% थे, अब मात्र 7.9% रह गए हैं। ये सभी हिंदू जो वहाँ कम हुए, वे धर्मांतरण नहीं हुए, उनमें से बहुतों ने प्रताड़ना के कारण भारत में शरण ली। और भारत में जो मुसलमानों की संख्या बढ़ी, उसका कारण यह है कि बहुत से मुसलमानों ने घुसपैठ की। गृह मंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रीय राजनीति में आया तो मुझे गुजराती

आती थी लेकिन कांग्रेस ने मुझे एक केस में फंसा दिया था जिसके कारण मुझे दिल्ली में गुजरात भवन में रहना पड़ता था। उस वक्त मेरे पास काम नहीं था और ज्यादा लोग बुलाते नहीं थे।

भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी : अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% रही।

पाकिस्तान-बांग्लादेश के हिन्दुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर: शाह

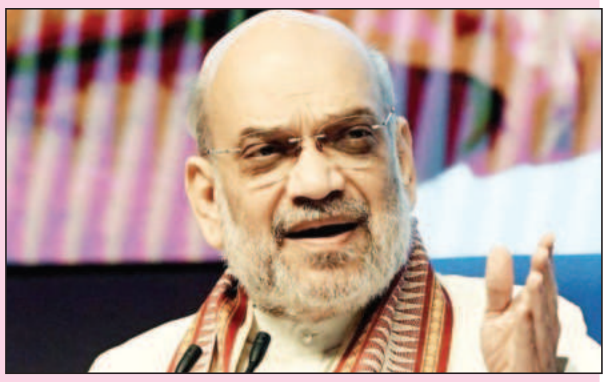

अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिये कौन हैं? जिन पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई और आर्थिक कारणों या अन्य कारणों से अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं, वे घुसपैठिये हैं। दुनिया में जो कोई भी यहाँ आना चाहे, अगर उसे आना दे दिया गया तो हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, उतना ही पाकिस्तानझबांग्लादेश के हिन्दुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। यह बात मैं देश के गृह मंत्री के रूप में कहता हूँ।

2014 तक की गलतियों का तर्पण किया : अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि 1951 से लेकर 2014 तक जो गलतियाँ हुई थीं, उनका एक प्रकार से तर्पण करने का काम मोदी जी ने किया था। नेहरू जी का वादा था शरणार्थियों को नागरिकता देने का, जिससे वे मुकर गए थे

कांग्रेस की सरकारों ने शरणार्थी बना दिया : अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद भारत के नेताओं ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि अभी दंगे हो रहे हैं, इसलिए अभी मत आओ; बाद में हम आपको नागरिकता देंगे। यह नेहरू-लियाकत पैक्ट का हिस्सा था। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें नागरिकता नहीं दी, उन्हें शरणार्थी बना दिया। जब मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तब हमने उन्हें नागरिकता दी अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदू 13% और अन्य अल्पसंख्यक 1.2% थे।

नीति आयोग ने सरकार के सामने रखा असंगठित कार्यबल की वित्तीय क्षमता बढ़ाने का रोडमैप

नई दिल्ली
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दौर में लगातार चर्चा है कि पेशेवरों को कितना नुकसान होगा और कितना लाभ। इस बीच नीति आयोग की नजर उस असंगठित क्षेत्र पर गई है, जिसकी कुल कार्यबल में 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का सहयोग है। आयोग के विशेषज्ञों का मत है कि एआइ सहित अन्य तकनीकी सहयोग इस क्षेत्र को दिया जाए तो असंगठित क्षेत्र के यह करीब 49 करोड़ कामगार विकसित भारत के लिए आर्थिकी की रीढ़ बन ग्रोथ इंजन साबित हो सकते हैं। डिजिटल

श्रमसेतु के नाम से राष्ट्रीय मिशन के प्रस्ताव के साथ आयोग ने केंद्र सरकार को रोडमैप भी सौंपा है, जिसमें क्षमता वृद्धि के लिए वर्ष 2035 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव या मील के पत्थर के रूप में चिन्हित किया गया है। एआइ फार इन्क्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट नाम से बनाए गए रोडमैप में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने स्पष्ट तौर पर अपना मत दिया है कि निर्माण, कपड़ा, खाद्य सेवाओं, देखभाल और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में अपनी बड़ी भूमिका के बावजूद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कम उत्पादकता वाले असुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं। एआइ और अन्य तकनीकें भारत के असंगठित व्यापार कार्यबल की क्षमता को अच्छी तरह सामने ला सकती हैं और उन्हें विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बदल सकती हैं, बशर्ते इन्हें सोच-समझकर और समावेशी तरीके से लागू किया जाए।

उद्योगों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

उत्सर्जन में कटौती अनिवार्य
नियम उल्लंघन पर जुर्माना
पर्यावरण संरक्षण की पहल

नई दिल्ली
सरकार ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत भारी कार्बन पैदा करनेवाले उद्योगों के लिए

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसके लिए इस साल 16 अप्रैल को मसौदा नियमों का प्रकाशन किया गया था और 282 औद्योगिक इकाइयों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इन उद्योगों में एल्यूमिनियम, सीमेंट, पल्प और पेपर और क्लोरअल्कली सेक्टर समेत तमाम इकाइयां शामिल हैं। उत्सर्जन को 2023-24 के बेसलाइन स्तर से लाना होगा नीचे इनको प्रति यूनिट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2023-24 के बेसलाइन स्तर से नीचे ले जाना होगा। नियमों के अनुसार, जो संयंत्र अपने निर्धारित लक्ष्य से कम उत्सर्जन करेंगे, वे व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करने वाले संयंत्रों को भारतीय कार्बन बाजार से उसी अनुपात में क्रेडिट खरीदना होगा या जुमार्ना देना होगा। जुमार्ने को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कहा जाएगा। ये अनुपालन वर्ष के दौरान कार्बन क्रेडिट के औसत व्यापार मूल्य से दोगुना होगा।

मायावती का पूरा देश करता है सम्मान: आजम खान

रामपुर
अखिलेश यादव से मुलाकात के तीसरे दिन ही सपा नेता आजम खां के सुर अचानक बदल गए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि, जरूरत पड़ने पर कभी भी उनसे मिलने की बात कही। साथ ही उनका इस बात को लेकर शुक्रिया भी अदा किया कि लखनऊ रैली के दौरान मायावती ने उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे उन्हें ठेस पहुंचती। आजम के इस बयान से सपा में हलचल बढ़ गई है। सीतापुर जेल में 23 महीने बिताकर लौटे सपा नेता आजम खां से बुधवार को अखिलेश यादव मिलने आए थे। दो घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों नेताओं ने आपस में किसी तरह के गिले-शिकवे न होने की बात भी कही थी। गुरुवार को रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खां पर तंज किया था। उन्होंने कहा था कि आजम की अब उम्र हो चुकी है, वह हमें क्या अपने शहर इमाम तक को नहीं पहचानते। इसके बाद शुक्रवार को आजम खां ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए बसपा प्रमुख मायावती प्रशंसा शुरू कर दी। कहा कि मैं ही नहीं उनका पूरा देश बहुत सम्मान करता है। वह एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। आगे कहा कि अगर मीडिया के माध्यम से उनके पास अगर कोई ऐसी खबर पहुंची है जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मुझे अफसोस है। उनकी अहमियत की मेरे दिल में कोई कमी नहीं है। कहा कि जब वह रैली में रामपुर आईं थीं तब वह मेरी मेहमान थीं। यह भी जोड़ा कि मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। कहा कि ये बात किसी को नहीं मालूम कि सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ता था तब काशीराम उनसे मिलने आते थे। आधा-एक घंटे बात करके जाते थे। इसके बाद फिर मायावती को लेकर कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो उनके लिए दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने।
उन्होंने कहा कि मुझे अगर उनसे मिलना होगा और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी जरूरतें हो सकती हैं, अखलाकी जरूरतें भी हो सकती हैं समाजी भी हो सकती हैं।

महागठबंधन में माकपा को 4, भाकपा को 8 और माले को 19 सीटें मिलने की उम्मीद

पटना
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वामपंथी दलों की तस्वीर साफ होती दिख रही है। माकपा को चार, भाकपा को आठ और भाकपा-माले को 19 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन माले से चार सीटिंग सीट को छोड़ने का प्रेशर भी है। इसमें औराई, तरारी, घोसी और पालीगंज शामिल है। इन सीटों पर राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, इन चार सीटों को भाकपा-माले छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है।
महागठबंधन के समन्वय समिति के

एक सदस्य ने बताया कि वामपंथी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉमूर्ला साफ है। सीटों के बंटवारे में जो देरी है वो कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी को लेकर है। हालांकि, भाकपा और माकपा भी क्रमशः तीन और दो अतिरिक्त सीटों की मांग को लेकर जोर लगाए है। भाकपा को तेघड़ा, बखरी, बछवाड़ा, बांका, झंझारपुर, रुपौली, बेलदौर और हरलाखी सीट देने पर सहमति बनी है। इसमें तेघड़ा (रामरतन सिंह) और बखरी (सूर्यकांत पासवान) उसकी सीटिंग सीट है। वैसे भाकपा द्वारा वारिसनगर, बिहारीशरीफ और गोह सीट पर दावेदारी की जा रही है।

जुबीन गर्ग के निजी सुरक्षा अधिकारियों की गिरफ्तारी

नई दिल्ली
जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को पिछले महीने सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि जुबीन गर्ग की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किए गए दो निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य को असम पुलिस ने मंगलवार को कई बार पूछताछ के बाद निलंबित कर दिया। उनके बैंक खातों के माध्यम से कई लाख रुपये के वित्तीय लेन-देन किए गए, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। इस गिरफ्तारी के साथ गर्ग की मौत के संबंध में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानू महंता, गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग, उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, संगीतकार शेखरज्योति और गायक महंता को गिरफ्तार किया गया था।

कोल्ड्रिफ सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले की जांच नहीं करेगी सीबीआई

नई दिल्ली
मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई। सीरप से हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में एक पीआईएल दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सीरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया था;

इसी याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि इस याचिका में विशाल तिवारी ने मांग करते हुए कहा कि ये लापरवाही की चरण सीमा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।

केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
बता दें कि सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह याचिका केवल समाचार पत्रों में पढ़ी गई खबरों पर आधारित है।
वहीं, उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या सबूत याचिकाकर्ता के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने याचिका खारिज की
उल्लेखनीय है कि इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने का कि बेंच मामले पर विचार करने को तैयार थी। हालांकि, जब यह जानकारी मिली कि याचिकाकर्ता ने पहले से ही 10 अन्य जनहित याचिकाएं दायर की है, तो अदालत ने नई याचिका खारिज कर दी।

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं

अंबेडकरनगर
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के प्रति जन जागरूकता के साथ बढ़ाई जाय, ताकि अधिक से अधिक पात्रों को लाभांवित किया जा सके। कहा कि प्रत्येक अधिकारी योजना की पात्रता एवं प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी रखे तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सोलर ऊर्जा के प्रति प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को मीटर रीडरों का प्रशिक्षण कराए जाने एवं ग्राम प्रधानों को योजना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों को अपने-अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित कर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने पंजीकृत वेंडरों से जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली और पावर कारपोरेशन एवं बैंकर्स को वेंडरों तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिया। कहा कि सभी विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए योजना को प्रभावी ढंग से क्रियांवित करें।

दिल्ली सरकार ने व्यापारी व उद्यमी को दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, सरकार अभी तक कारोबारियों को 694 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी कर चुकी है- सीएम

जीएसटी रिफंड तय समय सीमा में देने के लिए प्रतिबद्ध: रेखा

जीएसटी रिफंड वापस करने की प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य करना शुरू किया

नई दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापारी व उद्यमी को दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। सरकार अभी तक कारोबारियों को 694 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी कर चुकी है। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि छोटे-बड़े हर व्यापारी का जीएसटी रिफंड उसे तय समय सीमा में देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने इस वित्त वर्ष से व्यापारी वर्ग का जीएसटी रिफंड वापस करने की प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, व्यापार व कर विभाग ने इस वित्त वर्ष 2025-26 में (अप्रैल से अब तक) कुल 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर दिया है और कुल 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि व्यापारियों के खातों में जारी कर दी गई है, जो उनका हक था। सरकार ने एक रिकॉर्ड और भी बनाया है कि उसने सितंबर महीने में 227 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो दिल्ली के रिफंड इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर व्यापार में सुगमता (इज ऑफ डुईंग बिजनेस) वाली नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाएं तैयार की जा रही है। इसके साथ-साथ कारोबारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने और उनके कारोबार को बाधा-रहित चलाने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। उनकी सरकार मानती है कि राजधानी के कारोबारियों को व्यापार चलाने में जितनी सरलता मिलेगी, राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने का सपना उतनी ही तेजी से पूरा होगा। इसलिए व्यापारी वर्ग का रिफंड वापस करने के लिए तेज प्रयास जारी हैं।

दिल्ली को इको-टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में हमारा बड़ा कदम: कपिल

नई दिल्ली
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में तीन दिवसीय वैश्विक वन्यजीव मेले का शुभारंभ किया। दिल्ली का पर्यटन विभाग एशियन एडवेंचर्स के साथ मिलकर इस वैश्विक वन्यजीव मेले का आयोजन कर रहा है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन शहर में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स और इको-टूरिज्म विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पर्यटन मुख?य रूप से ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों (लाल किला से कुतुब मीनार) पर केंद्रित रहा है, पिछली सरकारों ने वन्यजीव पर्यटन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। यह तीन दिवसीय वैश्विक वन्यजीव मेला 12 अक्टूबर तक चलेगा।

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रकृति, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के इस अद्भुत आयोजन में शामिल हुई है। दिल्ली को इको-टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में यह हमारा बड़ा कदम है। दिल्ली में पक्षियों और स्तनधारियों की अनेक प्रजातियों के साथ ही समृद्ध बायोडायवर्सिटी पार्क, यमुना रिवरबैंक और बड़ा रिज क्षेत्र है। पिछले दो-तीन दशकों से जैव विविधता और पर्यटन के इस पहलू को पूरी तरह से अनदेखा किया गया था।

दिल्ली में गिरी एक और इमारत, दो मंजिला मकान के मलबे में दबे कई लोग

नई दिल्ली
उत्तम नगर के होली चौक आजाद डेयरी के पास शुक्रवार दोपहर एक दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दब गए। घटना होते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत राहत बचाव के साथ साथ घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत से जुड़ी अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर में बचाव दल ने मलबे से एक 12 साल की बच्ची और महिला को बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया। दमकल अधिकारी के मुताबिक बच्ची को मामूली चोट लगी है, वहीं महिला बेहोशी की हालत में है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए उसे हटाने का काम जारी है। दमकल अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3:10 बजे दमकल विभाग को होली चौक उत्तम नगर के पास एक दो मंजिला इमारत गिरने और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मकान गिरने की आवाज आने के बाद आस पास के लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचे और मलबा हटाने का काम करने लगे।

कोर्ट ने राजपाल की दुबई यात्रा की अनुमति याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस और एक निजी कंपनी से जवाब मांगा है। राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में दायर याचिका के तहत दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति रवींद्र दूडेजा ने राजपाल यादव की अर्जी पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर के लिए तय की। यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है।

प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नियंत्रण पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका

हाई कोर्ट ने सरकार के अधिकार सीमित किए

मुनाफाखोरी रोकने के लिए फीस नियंत्रण संभव

निदेशालय शुल्क विवरण की जांच कर सकता है

नई दिल्ली
निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस बढ़ाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमारेखा तय कर दी। दो निजी स्कूलों के मामले में एकल पीठ के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) को निजी स्कूलों के फीस ढांचे को मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता तक रेगुलेट करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ऐसे निजी स्कूलों पर न तो व्यापक प्रतिबंध लगा सकती है और न ही फीस वृद्धि के संबंध में आदेश दे सकती है। दो सदस्यीय पीठ ने इस टिप्पणी के साथ एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली शिक्षा निदेशालय व विभिन्न छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल और लीलावती विद्या मंदिर को 2017-18 शैक्षणिक सत्र के लिए शुल्क बढ़ाने से रोकने वाले आदेशों को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्कूलों की ओर से ली जाने वाली फीस को सरकार की ओर से रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन रेगुलेशन की अनुमति केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि स्कूल मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण या कैपिटेशन शुल्क वसूलने में लिप्त न हों। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी फीस संरचना उपलब्ध बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और संस्थान के विस्तार या बेहतरी की भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। शुल्क विवरण की जांच करने पर शिक्षा निदेशालय यह पाता है कि स्कूलों द्वारा एकत्रित राशि का व्यय शिक्षा निदेशालय-1973 या उसके तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं हो रहा है तो स्कूल के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

अवैध खनन से यमुना को खतरा

नई दिल्ली
दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना में हो रहे अवैध खनन से जुड़े मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रशासन को संयुक्त रूप से खनन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। यमुन में खनन से जुड़ी एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेकर एनजीटी ने मामले में सुनवाई शुरू की थी। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा दाखिल किए गए हलफनामा पर गौर किया। साथ ही, जिला खनन अधिकारी को अगली सुनवाई से एक दिन पहले एनजीटी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि संयुक्त अंतर-राज्यीय टास्क फोर्स के लिए नामित अधिकारियों की सूची पेश करें। साथ ही दिल्ली-उत्तर प्रदेश की संयुक्त अंतर-राज्यीय टास्क फोर्स को संयुक्त निरीक्षण एवं बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया। एनजीटी ने निर्देश दिया कि मामले की कई कार्रवाई व बैठकों की कार्यवृत्त पेश करें।

चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली
पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने शुक्रवार को वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया है। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) दीप्ति देवेश को सुनवाई के लिए सौंपा गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को न्यायाधीश अतुल अहलावत ने चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। जिसके बाद मामला जिला न्यायाधीश को भेजा गया। चैतन्यानंद छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उसने जमानत की अर्जी दायर की है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। 28 सितंबर को कोर्ट ने उनसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद तीन अक्टूबर को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती से उस मामले में पूछताछ की थी, जिसमें उस पर वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। इससे पहले, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य मामले में भी एएसजे अतुल अहलावत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। बाद में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था।

इसी बीच, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट जवाब मांगा है कि जेल में चैतन्यानंद सरस्वती को गेरुआ वस्त्र पहनने और धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दायर जवाब उचित नहीं है और उसमें जेल मैनुअल के किसी प्रविधान का उल्लेख नहीं किया गया है। गेरुआ वस्त्र और धार्मिक पुस्तकों से संबंधित आवेदन पर सुनवाई भी सोमवार को ही की जाएगी।

टेंपो मालिक की चाकू से गोदकर हत्या, झगड़े के बाद ड्राइवर ने ही किए वार

नई दिल्ली
बुध विहार थाना क्षेत्र में लेनदेन के विवाद में चालक ने अपने ही टेंपो मालिक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने मालिक के घर पर ही वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मृतक के 14 वर्षीय बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी ड्राइवर शक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली का चांदनी चौक बाजार त्योहारी सीजन में गुलजार

नई दिल्ली
दिल्ली का प्रमुख थोक बाजार चांदनी चौक त्योहारी खरीदारी से गुलजार है। दिल्ली और विभिन्न राज्यों से थोक और खुदरा खरीदार कपड़े, सजावटी बिजली के उत्पाद, पर्दे, चादरें, घरेलू सजावट के सामान और आभूषण सहित अन्य सामान खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। हालाँकि, रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण, ट्रैफि क जाम और सेंट्रल वर्ज पर भिखारियों और बेघर लोगों की मौजूदगी इन खरीदारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। इसी तरह, कूड़े के ढेर, लटकते तार, दीवारों पर रंग उड़ाते पोस्टर और झंडे, और पान की पीक इस ऐतिहासिक बाजार की सुंदरता को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदार इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। बाजार की यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ही नागरिक एजेंसियों की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक का निरीक्षण किया।

नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले

नई दिल्ली
त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रेलवे के लिए इस स्थिति से निपटना एक चुनौती बन गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अजमेरी गेट के पास एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा, 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म संख्या 16 से चलेंगी। आवश्यकतानुसार अन्य प्लेटफॉर्म से भी ट्रेनें चलेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जा रही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कम समय में बहुत अधिक ट्रेनें न आएं और न ही स्टेशन पर आएं। इससे प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर भीड़भाड़ बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, 30 अक्टूबर तक शताब्दी और लोकल ट्रेनों सहित 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों के वर्तमान और बदले हुए प्लेटफॉर्म की जानकारी

ट्रेन	वर्तमान प्लेटफॉर्म	बदला हुआ प्लेटफॉर्म
नई दिल्ली-दरभंगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562)	13	1
दरभंगा-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561)	12	7
बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस (12260)	13	9

हवा में एक फीसदी पीएम 2.5 बढ़ने से 9.6% बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के मामले

नई दिल्ली
भारत में बढ़ता वायु-प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़ों और दिल के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार, हवा में पीएम 2.5 के स्तर में सिर्फ एक माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी मानसिक बीमारियों के मामलों में तेज इजाफा करती है। इस मामूली बढ़ोतरी से हर एक लाख लोगों में डिप्रेशन के 9.6%, एंजाइटी के 5.3% और तनाव से जुड़ी परेशानियों के 2.6% नए मामले सामने आते हैं। सिर्फ बाहर की हवा ही नहीं, घर के अंदर की हवा भी बच्चों के दिमाग के लिए उतनी ही हानिकारक साबित हो रही है।

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के शोध में पाया गया कि भारत की इनडोर वायु गुणवत्ता दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बाधित कर रही है। वएअ के प्रमुख शोधकर्ता जॉन स्पेंसर के अनुसार, ग्रामीण भारत के घरों में ढट2.5 की अधिकता से न सिर्फ बच्चों की सीखने-समझने की क्षमता घटती है, बल्कि भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में पहले से ही पीएम 2.5 का औसत स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 5 से 10 गुना अधिक है, और हर साल यह खतरा और भी गहराता जा रहा है। लीड्स विश्वविद्यालय के पृथ्वी एवं पर्यावरण स्कूल के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, 2050 तक भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट बन जाएगा। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। सर्दियां शुरू होते ही देश के कई शहर गंभीर वायु प्रदूषण के संकट से जूझने लगते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 16 लाख लोगों की मौत होती है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारतीयों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते 2050 तक हवा में इसकी मात्रा दोगुनी तक बढ़ सकती है। इससे एक गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है।

सफर में बीमार पड़ने पर सुलभ होगा इलाज, ट्रक ड्राइवरों के लिए 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च

नई दिल्ली
देश की सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ते ट्रक, शहरों तक अनाज और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इन ट्रकों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। हाईवे पर अस्पतालों और तत्काल मदद की कमी उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। इसी समस्या को समझते हुए, अपोलो टायर्स ने अपनी हेल्थकेयर पहल के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च किया है, जो ट्रक ड्राइवरों के लिए एक डिजिटल वरदान साबित होगा। यह एप ट्रक ड्राइवरों को सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकों से सीधा संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे वे तत्काल चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय पर इलाज और मार्गदर्शन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, 'स्वास्थ्य सारथी' एप की मदद से ड्राइवर अपने मार्ग में पड़ने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों का भी पता लगा सकेंगे, जो आपात स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अपोलो टायर्स के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर राजीव कुमार सिन्हा और इंडिया, सार्क एवं साउथ-ईस्ट एशिया के कॉमर्शियल वाइस प्रेसिडेंट राजेश दहिया ने इस पहल के बारे में जानकारी दी।

संपादक की कलम से

बिहार चुनाव: क्या पटना में कांग्रेस बिखरी जातियों को एकजुट कर पाएगी?

बिहार में कई पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है लेकिन उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. ये समुयअनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कांग्रेस इस दलित केंद्रित राजनीति का धुरी बनना चाहती है. उसने रविदास समुदाय के नेता को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है. लेकिन क्या वह इन बिखरी जातियों को एकजुट कर पाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक का पटना में आयोजन इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस बिहार को लेकर गंभीर है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, कांग्रेस को बिहार में नीतीश और भाजपा की 20 साल की सरकार के खिलाफ एंटीइनकम्सी का फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है।

बिहार में रविदास जाति की ज्यादातर जनसंख्या उन ज़िलों में हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ सटे हुए हैं, जैसे सासाराम, सिवान,गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, बक्सर आदि. संभवतः यही कारण है कि 1990 के दशक के आखिरी और 2000 के दशक के दौरान जब उत्तर प्रदेश में मायावती मजबूत हुई तब बिहार में भी बसपा के विधायक बनने लगे थे।

साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती के दो उम्मीदवार चुनाव जीते थे जो 2000 में बढ़कर 5 तक हो गए. अक्तूबर 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तब भी बसपा के चार विधायक थे. इस तरह से जैसे जैसे बिहार में कांग्रेस और राजद कमजर हुई, बसपा मजबूत हुई. लेकिन जब नीतीश कुमार ने बिहार में महादलित का कार्ड खेला तब बसपा 2010 और 2015 के चुनाव में एक भी सीट नहीं हासिल कर पायी. इस दौरान बसपा भी धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में विलुप्त होने लगी।

बिहार की तीन सबसे बड़ी दलित जातियों में से 5.31% वाले पासवान और 3.09% वाले मुसहर के पास अपना नेता और अपना पार्टी है लेकिन 5.25% वाले रविदास के पास न तो कोई नेता है न कोई पार्टी है. बिहार में ऐसी और भी कई जातियां है जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है लेकिन उनके पास न कोई नेता है और न ही कोई पार्टी है. बिहार कांग्रेस इन नेता विहीन और दलविहीन जातियों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रही है जिसमें राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाना और आईपी गुप्ता जैसे पान नेता को आगे लाना और कन्हैया कुमार के सहारे सभी पार्टियों से मोहभंग हो चुके भूमिहारों के बीच थोड़ी बहुत साख दुबारा पाने का राजनीतक प्रयास है।

जीएसटी बचत महोत्सव में भी किसान की जेब खाली

डॉ. राजाराम त्रिपाठी

जब चाकू सरकार का और खरबूजा किसान का तो, किसान की जेब कटना तय है

पाँच मुख्य बिंदु :

सरकार ने ट्रैक्टर टायरों का जीएसटी घटाया, पर छोटे किसानों के उपकरणों पर बोझ जस का तस।

18% जीएसटी वाले छोटे कृषि यंत्रों को घटाने की मांग अब भी अनसुनी।

पुराने रेट पर खरीदे माल की इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी पर कोई नीति स्पष्ट नहीं।

बढ़ती मजदूरी, जलवायु परिवर्तन और काम के घटते घंटे ने लागत दोगुनी कर दी।

बचत महोत्सव के बीच भी किसान की बचत सिर्फ सरकारी पोस्टरों तक सीमित।

पूरा भारत आज जीएसटी बचत महोत्सव मना रहा है! पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और टीवी विज्ञापनों से देश का कोना-कोना पटा पड़ा है। छोटे गाँवों की चौपालों से लेकर महानगरों की मेट्रो तक, हर ओर सरकार के उत्सव का डंका बज रहा है। लेकिन सवाल यह है ,, किसकी बचत? किसान की या सरकार की?

सरकार कह रही है कि उसने 56वीं जीएसटी परिषद बैठक के बाद जीएसटी 2.0 लाकर जनता को राहत दी है। पर जब इस राहत की परतें खोलते हैं तो कृषि क्षेत्र के लिए यह राहत महज कागजी साबित होती है।

कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दोहरी मार :-

ट्रैक्टर के टायर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, परंतु वही टायर यदि छोटे किसान के मिनी-टिलर, पंपसेट या ब्रश कटर में लगे हों, तो अब भी वही पुराना 18% टैक्स बरकरार है। यही नहीं ,, वॉटर पंप (ल्रठ 8413), राइस मिल (8437), ब्रश कटर, हेज ट्रिमर, चेन सॉ, पोल प्रूनर जैसे छोटे किसानों के उपकरण आज भी 18% जीएसटी के घेरे में हैं।

ये वही यंत्र हैं जिनसे छोटा किसान खेती में आत्मनिर्भर बन सकता था, पर सरकार ने इन्हीं पर सबसे ऊँचा टैक्स रख दिया।

बड़ा किसान ट्रैक्टर खरीदे तो राहत, छोटा किसान सिंचाई हेतु मोटर खरीदे तो सजा!

क्या यही सबका साथ, सबका विकास का नया संस्करण है?

भारत में लगभग 84% किसान छोटे या सीमांत किसान हैं, जिनकी औसत जोत 2झ3 एकड़ है। इनकी उत्पादन लागत हर साल 12झ15% बढ़ रही है, जबकि आय वृद्धि की दर मुश्किल से 2झ3% है। ऐसे में 18% जीएसटी उनकी कमर तोड़ रहा है।

खेती की लागत में लगी आग और काम के घटते घंटे :-

आज खेती की लागत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल,, ओ सबके दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ पिछले पाँच वर्षों में डीजल के दाम में लगभग 45% वृद्धि हुई है, और उर्वरक की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कारणों से दोगुनी हुई हैं।

मजदूरी भी दोगुनी हो चुकी है, लेकिन काम के घंटे घट गए हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण दोपहर का तापमान 45झ47त्ठ तक पहुँच रहा है, जिससे खेतों में काम करने का औसत समय 8झ9 घंटे से घटकर 5 घंटे रह गया है।

अब किसान को वही काम कराने के लिए दो मजदूर रखने पड़ रहे हैं ,, जिससे प्रति एकड़ लागत में लगभग 30झ40% की वृद्धि हो चुकी है।

देश में छुट्टियों का भी अजीब रोग फैल गया है ,, कभी कोई दिवस, कभी किसी की जयंती दिवस, आए दिन विभिन्न धर्मों के तिथि एवं त्यौहार , और अब तो हर तिथि पर कोई न कोई समारोह। इन छुट्टियों आयोजनों एवं समारोहों के चलते साल के 365 दिन कम पड़ रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी छुट्टी मनाते हैं, और किसान खेत में पसीना बहाता है। पर सरकार की नीतियों में उस पसीने का कोई मूल्य नहीं।

विडंबना यह है कि छुट्टी मनाने की यह बीमारी अब गाँव के कृषि मजदूरों में भी तेजी से फैल रही है।

ऐसे में कृषि को टिकाऊ बनाए रखने के लिए मानव श्रम की जगह छोटी कृषि मशीनों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है पर सरकार उन्हें टैक्स से मुक्त करने की जगह बोझिल बना रही है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेच : या तो सरकार जीते, या फिर व्यापारी, किसान को तो हारना ही है :-

एक और बड़ा अन्याय अूॅ४ह्लंशेी कल्लस्र४३ उ१ीेि३ से जुड़ा है।

जो व्यापारी पहले 18% जीएसटी पर माल खरीद चुका था, अब वही माल 5% रेट पर बेचना पड़ रहा है।

पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अतिरिक्त 13% का रिफंड नहीं देगी (ऊ१ू४ह्ल१ ठङ्क. 135/05/2020झ्रॠरळ)।

अब व्यापारी घाटा तो झेलेगा नहीं ,,, वह मूल्य बढ़ाकर किसान से वसूलेगा।

रानी दुर्गावती: नारी शक्ति की वह मशाल, जो सदियों से जलती आ रही है

लेखिका : श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार

भारत के मंत्रालयों, नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों की कल्पना से भी सदियों पहले, गोंड साम्राज्य की एक आदिवासी युवा रानी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी रही – जिसने आत्मसमर्पण के बजाय सम्मान, साहस और कर्तव्य का मार्ग चुना। भारत में वीरता और पराक्रम की प्रतीक के रूप में याद की जाने वाली रानी दुर्गावती आज भी सार्वजनिक जीवन, व्यवसाय, विज्ञान और नागरिक सेवाओं को नई दिशा देने वाली महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। उनकी 501वीं जयंती के अवसर पर, हम उस गाथा और उन मूल्यों को याद करते हैं, जो 16वीं शताब्दी के युद्धक्षेत्रों से लेकर आधुनिक भारत की नीतियों तक एक सतत प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।

साहस की प्रतिमा

रानी दुर्गावती का जीवन एक किंवदंती इसलिए बना, क्योंकि उन्होंने इतिहास में निष्क्रिय पात्र बनकर रहने से इनकार कर दिया। आक्रमणकारी मुगल शक्तियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लिया। एक ऐसी महिला, जिसने नेतृत्व किया, निर्णय लिए और अंततः बलिदान दिया – रानी दुर्गावती ने स्वयं को एक क्षेत्रीय शासक से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। आज, चाहे उन्हें लोककथाओं, स्मारकों या मध्य भारत की संस्कृति में याद किया जाए, वे इस सत्य की जीवंत मिसाल हैं कि नेतृत्व किसी एक लिंग की सीमाओं में नहीं बँधता।

प्रतीक से नीति तक: भारत इस कर्तव्य का निर्वहन करता है

आधुनिक भारत में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की जो संरचना आज दिखाई देती है – जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संबद्ध विभागों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है – वह उसी कर्तव्य भावना और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्रेरित है, जिसका उदाहरण रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार रानी ने अपने समय में राज्य और प्रजा की रक्षा का दायित्व निभाया, उसी प्रकार आज की सरकार विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं के अधिकारों, अवसरों और समान भागीदारी की रक्षा और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा और सामाजिक समरूपता:

लड़कियों की शिक्षा में सुधार और लैंगिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से लागू किए गए कार्यक्रम आज समाज की नींव को मजबूत कर रहे हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता:

कौशल विकास पहलों से लेकर ऋण और बाजार तक पहुँच प्रदान करने वाली योजनाएँ महिलाओं को उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बना रही हैं। ये प्रयास आधुनिक शासन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

सुरक्षा और कानूनी संरक्षण: वन स्टॉप सेंटर और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाएँ महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

इन पहलों ने यह सिद्ध किया है कि भय या असुरक्षा किसी महिला की प्रगति और आवाज को सीमित नहीं कर सकती।

स्वास्थ्य और मातृ देखभाल: मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाएँ केवल स्वास्थ्य सेवा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे महिलाओं के समग्र कल्याण का प्रतीक हैं। ये प्रयास महिलाओं को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए सशक्त करते हैं।

जमीनी स्तर पर शासन और प्रतिनिधित्व: पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहलें लोकतांत्रिक शासन को और समावेशी बना रही हैं। यह उसी राजनीतिक दूरदर्शिता की झलक है, जो रानी दुर्गावती ने अपने राज्य के संचालन में प्रदर्शित की थी।

जीवन और उपलब्धियों में मापी गई प्रगति

पिछले कुछ दशक उल्लेखनीय प्रगति के साक्षी रहे हैं - महिला साक्षरता और कार्यबल में भागीदारी में वृद्धि, निर्वाचित पदों पर महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति, उद्यमिता में तेजी से उभार, और सुरक्षा एवं समान अवसरों के प्रति समाज की बढ़ती संवेदनशीलता ने भारत को एक नई दिशा दी है। ये बदलाव केवल आँकड़े भर नहीं हैं; ये उसी सिद्धांत की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं जो रानी दुर्गावती के जीवन ने सिखाया था कि जब महिलाएँ हर परिस्थिति के लिए सुसज्जित और सशक्त होती हैं, तो वे समाज को नया आकार देती हैं।

रानी दुर्गावती की विरासत एक आधारशिला

रानी दुर्गावती के उदाहरण को विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाता है उनका दोहरा स्वरूप - नैतिक और व्यावहारिक। नैतिक स्तर पर वे गरिमा, साहस और ज़िम्मेदारी की प्रतीक हैं, जबकि व्यावहारिक स्तर पर उनका जीवन महिलाओं को निर्णयकर्ता और लोककल्याण की रक्षक के रूप में स्थापित करता है। यह दोहरी विरासत पीढ़ियों से भारत की नागरिक चेतना का हिस्सा रही है और इसी ने महिला सशक्तिकरण की नीतियों और पहलों को समाज में गहरी जड़ें जमाने में सहायता की है।

विकसित भारत के लिए नया दृष्टिकोण

जैसे-जैसे देश विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, उसे विकास को महिलाओं की भागीदारी के पैमाने और समानता के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। महिला-केंद्रित विकसित भारत में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी को विकास के लिए एक अतिरिक्त साधन नहीं, बल्कि विकास का मुख्य सूचक माना जाएगा। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ है कि देश की प्रगति को केवल प्रमुख कल्याण संकेतकों से नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों - बोर्ड, लोक सेवा और सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी से भी मापा जाएगा।

इस प्रकार, उन नीतियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो अवैतनिक देखभाल - जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और सामुदायिक सहायता - के बोझ को कम करें, ताकि महिलाओं के पास सार्वजनिक और आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध हो।

इस प्रकार, अतीत के साहस को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ते हुए, रानी दुर्गावती की कहानी केवल एक धरोहर नहीं है, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत क्या बन सकता है। उनका साहस यह संदेश देता है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और भविष्य को आकार देने का समान अधिकार है। आज, भारत के मंत्रालयों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का दायित्व है कि वे उस अधिकार को- स्कूलों और अस्पतालों के माध्यम से, कानूनों और आजीविकाओं के माध्यम से, सुरक्षित सड़कों और समान बोर्डों के माध्यम से - रोजमर्रा की वास्तविकता में बदलें। यदि विकसित भारत की नब्ज उसकी महिलाओं की शक्ति से मापी जाती है, तो रानी दुर्गावती को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वह शक्ति हर महिला तक पहुँचाई जाए।

अंततः, रानी की सबसे महान विरासत कोई पत्थर का स्मारक नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्र है जहाँ लाखों महिलाएं जीवन के हर मंच से - चाहे वह घर हो, बाजार हो, विज्ञान हो या शासन - नेतृत्व करें। वे 21वीं सदी में साहस और नेतृत्व की परंपरा को आगे बढ़ाएं।

मानसिक स्वास्थ्य है रोगमुक्त जीवन की मुस्कान

ललित गर्ग

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष हमें यह सोचने का अवसर देता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका मन है, और जब मन अस्वस्थ होता है तो समूचा जीवन बिखर जाता है। इस वर्ष की थीम है संकट और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना। यह थीम प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, जो मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने और संकटग्रस्त लोगों के लिए प्रभावी सहायता तंत्र स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करती है। आज दुनिया ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही है जहाँ महामारी, युद्ध, आर्थिक संकट, सामाजिक अस्थिरता, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएँ लगातार मनुष्य के मन पर चोट कर रही हैं। इन आपदाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक मौन महामारी बन गई है। भारत में यह चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कम है और कलंक अधिक। मानसिक स्वास्थ्य दिवस सभी के लिए है-यह वर्ष के 365 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन 10 अक्टूबर दुनिया भर के सभी लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने हेतु एकजुट होने का एक अवसर है। यह सभी को अधिक समझ और सहानुभूति के माध्यम से अपने और दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आज का युग आभासी दुनिया का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल साधनों ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतना ही जटिल भी। आभासी संबंधों ने संवाद के नए मार्ग खोले हैं, परंतु भावनाओं की सच्चाई को खोखला कर दिया है। हम हर समय आभासी दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत अकेले हो गए हैं। दूसरों के सुख और सफलता के प्रदर्शन से तुलना और हीनता की भावना बढ़ती जा रही है। इस निरंतर प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन ने लोगों के मन में चिंता, अवसाद और असंतोष को गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया का अति प्रयोग मनुष्य को कल्पना और भ्रम की दुनिया में धकेल रहा है, जहाँ असली जीवन की सादगी और आत्मीयता खोती जा रही है। युवा पीढ़ी सबसे अधिक मानसिक दबाव में है। प्रतिस्पर्धा, परीक्षा, करियर और परिवार की अपेक्षाएँ उन्हें उस स्तर तक पहुँचा रही हैं जहाँ असफलता आत्मघाती कदमों में बदलने लगी है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में सबसे बड़ी संख्या किशोरों और युवाओं की है। वे जीवन से नहीं, अपनी असफलता से भागना चाहते हैं, परंतु संवादहीनता, समझ की कमी और मानसिक परामर्श की अनुपलब्धता उन्हें अंधकार की ओर धकेल देती है। युवा जीवन में ऊर्जा और आशा के प्रतीक हैं, लेकिन जब उन पर अपेक्षाओं का बोझ हावी हो जाता है, तब वही ऊर्जा

विनाशकारी रूप ले लेती है। परिवार और समाज को चाहिए कि वे उन्हें समझें, संवाद करें, उनके मन की सुनें, और उन्हें यह विश्वास दें कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर है।

महिलाओं की स्थिति भी कम कठिन नहीं है। घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों, सामाजिक बंधनों और लैंगिक भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहरे रूप से प्रभावित किया है। घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता की स्थितियाँ उन्हें भीतर से तोड़ देती हैं। फिर भी वे समाज की धुरी बनी रहती हैं। उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना, उनके लिए सुरक्षित वातावरण और परामर्श की सुविधाएँ उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब महिलाएँ स्वस्थ और संतुलित मन से कार्य करेंगी, तभी समाज स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह वृद्धों का जीवन भी मानसिक स्वास्थ्य के मामले में अधिक जटिल होता जा रहा है। आत्महत्या की बढ़ती घटनाएँ एक चेतावनी हैं कि हम किसी बड़ी भूल के शिकार हैं। यह केवल व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्पण है। जब कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब उसकी आत्मा में आशा का दीप बुझ जाता है। उसे बचाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके पास जाएँ, उसकी बात सुनें, उसे यह एहसास दिलाएँ कि वह अकेला नहीं है। समाज, परिवार, शिक्षण संस्थान और सरकार सभी को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ निराश व्यक्ति के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध हो। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव-गाँव तक पहुँचें, स्कूलों और कार्यस्थलों में परामर्श केंद्र स्थापित हों, यह समय की पुकार है।

नशा मानसिक अस्वास्थ्य का सबसे बड़ा सहचर बन चुका है। शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, यहाँ तक कि दवाओं के दुरुपयोग ने मनुष्य की चेतना को कुंद कर दिया है। नशा अस्थायी आनंद देता है, परंतु दीर्घकालिक विनाश का कारण बनता है। यह व्यक्ति की आत्मनियंत्रण शक्ति को नष्ट कर देता है, निर्णय क्षमता को कमजोर करता है और अवसाद तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति समाज से कट जाता है और उसकी आत्मा में एक गहरा शून्य भर जाता है। इस समस्या का समाधान केवल दंड से नहीं, बल्कि संवेदनशील पुनर्वास और मानसिक परामर्श से संभव है। समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति शिक्षित करना और युवाओं को इसके जाल से बचाना हर घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मानसिक अस्वस्थता से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यकता होती है आशा की। निराशा की अंधेरी सुरंग में यदि कोई हाथ थाम ले, यदि कोई मुस्कान दे दे, यदि कोई कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, तो वही वाक्य जीवनदान बन सकता है। आत्महत्या की रोकथाम का आरंभ संवेदनशील संवाद से होता है। हमें अपने बच्चों, मित्रों, सहकर्मियों और परिवारजनों से यह रिश्ता बनाना होगा कि वे अपने मन की बात कह सकें, बिना किसी भय या लज्जा के।

आज का हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। तनाव उनको होता है, जो निरंतर मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, विश्राम नहीं करते। यानी कि आज की भाषा में जो बिजी रहते हैं। बिजी रहने की इस आदत ने जीवन में बहुत टेंशन पैदा किए हैं। जीवन में बिजी के साथ ईजी होना जरूरी है क्योंकि एक पहिए से रथ नहीं चलता। उसके लिए दोनों पहिए चाहिए। ज्ञान और ध्यान, काम और आराम- ये जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक पहिए को निकाल देंगे तो रथ नहीं चलेगा। आज यही तो समस्या है और यही मानसिक अस्वास्थ्य की जड़ है। जीवन को एकांगी बनाया जा रहा है। इससे बहुत भारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन की चंचलता का तो ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किया जा रहा है, पर उसे स्थिर बनाने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। समस्या स्थिरता में नहीं, चंचलता में होती है। बाहर का खोल जितना भी मजबूत हो, भीतर को साधे बिना चंचलता कम नहीं होती। ये भीतर की गांठें देर-सबेर उलझा ही देती हैं। आज आवश्यकता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता समझें। शरीर की बीमारी के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की पीड़ा के लिए भी विशेषज्ञ सहायता लेना सामान्य बने। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को विद्यालयों में जोड़ा जाए, परामर्श केंद्रों को सशक्त किया जाए, और हर नागरिक को यह संदेश दिया जाए कि सहायता लेना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि चेतना का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज का आधार है। हमें निराशा से आशा की ओर, अकेलेपन से अपनत्व की ओर और अस्वस्थता से संतुलन की ओर बढ़ना है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है, और जब मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होगा, तभी जीवन भी सुंदर होगा। इसलिए आइए, हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने और दूसरों के मन की सेहत का ध्यान रखेंगे, संवाद करेंगे, सहयोग करेंगे और हर उस व्यक्ति के लिए आशा का दीप जलाएँगे जो अंधेरे में भटक रहा है। यही इस दिवस का सच्चा संदेश और जीवन का शाश्वत सार है।

राजस्थान के लिए नया वर्ष 2026 विकास का नया सूरज लेकर आयेगा

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान के लिए नया वर्ष 2026 विकास का नया सूरज लेकर आयेगा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में माही बाँध के बैकवाटर क्षेत्र बांसवाड़ा-रतलाम (मध्य प्रदेश) मार्ग पर 72,000 करोड़ रू की लागत से बनने वाले परमाणु बिजली घर की नापला गाँव में आयोजित एक कार्यक्रम में आधारशिला रख प्रदेश को दिवाली का तोहफा दिया था और अब वे एक बार फिर पश्चिम राजस्थान की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने के लिए नए साल से पहले राजस्थान की यात्रा पर आ सकते है और राजस्थान को पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के रूप में नए वर्ष का नायाब उपहार दे सकते है।राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को गुजरात के सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए है कि राजस्थान में दिसंबर से पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल की शुरूआत होगी और सरकार निवेशकों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एवं डेटा सेंटर्स स्थापित करने में सहयोग देगी। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के निकट पचपदरा में स्थापित की जा रही इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपये है, जो इसे देश की सबसे महंगी रिफाइनरी परियोजनाओं में से एक बनाती है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी

एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना है। यह परियोजना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है । एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है इस रिफाइनरी में प्रतिदिन 9 मिलियन टन (एमटीपीए) कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता होगी। इसमें पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी जैसे उत्पादों के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल यूनिट भी शामिल है, जो पॉलीप्रोपाइलीन जैसे रासायनिक उत्पाद तैयार करेगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि स्थानीय उद्योग, परिवहन और विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भी तेजी से विकास की बहार आएगी।इस रिफाइनरी से राजस्थान को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

राज्य को न केवल ईंधन उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिलेगी बल्कि यह प्लांट उत्तर भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। इसके साथ-साथ भारत की आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता घटेगी और प्रधानमन्त्री मोदी के वोकल फॉर लोकल की भावना को भी बल मिलेगा।निश्चित रूप से, पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होगी। सूरत में मुख्यमंत्री शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस की भी चर्चा की और इसमें भाग लेने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को निमंत्रण दिया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार इस वर्ष से हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने प्रवासी उद्यमियों को आईटी, फार्मा, ऊर्जा, टेक्सटाइल, खनन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने को राजस्थान आने का आमंत्रण दिया।

लेबनान में इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में 32 लोग गिरफ्तार

एजेंसी

बेरूत। लेबनान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से नौ के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया है, जबकि 23 अन्य अभी भी जांच के घेरे में हैं। इन सभी पर हिज़्बुल्लाह के बारे में इज़राइल को जानकारी देने का संदेह है। एक न्यायिक अधिकारी ने समाचार पत्रों को यह जानकारी दी। नाम न छापने के अनुरोध पर अधिकारी ने बताया कि इज़राइल के साथ सहयोग करने के संदेह में कम से कम 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से छह युद्धविराम से पहले के हैं। अधिकारी ने कहा कि अब तक, नौ लोगों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा चुका है, जबकि 23 अभी भी जांच के घेरे में हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह समूह के शस्त्रागार पर हमला किया और उसके कई वरिष्ठ कमांडरों को ढेर कर दिया। वह नवंबर में हुए युद्धविराम के बाद भी समूह पर हमले जारी रखे है। लेबनान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इज़राइल के साथ युद्ध में है और देश के नागरिकों द्वारा इजराइल से किसी भी तरह का संपर्क रखने पर कारावास की सजा का प्रावधान रखता है।

मैक्रॉ 48 घंटे में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे

पेरिस। फ्रांस में गहराते राजनीतिक संकट का हल निकालने के प्रयासों के तहत राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉ ने घोषणा की है कि वह अगले 48 घंटे में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। उनका यह फैसला प्रधानमंत्री के तौर पर सेबेस्टियन लेकोर्नू के अचानक इस्तीफे के बाद आया, जिन्होंने महज 26 दिनों में पद छोड़ दिया। यह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का अबतक का सबसे छोटा कार्यकाल है। मैक्रॉ ने बुधवार को इस आशय की घोषणा की कि वह दो दिनों के अंदर ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मैक्रॉ के करीबी और पूर्व रक्षा मंत्री लेकोर्नू ने सोमवार को एक मध्यमार्गी विचारधारा समर्थक मंत्रिमंडल का ऐलान किया था जिसकी सत्तारूढ़ और विरोधी सभी दलों ने कड़ी आलोचना की। आलोचकों ने पूर्व वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर जैसे चेहरों को बरकरार रखने पर तीखा हमला बोला, जिन्होंने कर्ज संकट के बीच कटौती नीतियों को जारी रखा था। हालाकिं मैक्रॉ के अनुरोध पर लेकोर्नू ने 48 घंटे तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए दक्षिण पंथी और वाम पंथी नेताओं से परामर्श कर स्थिरता योजना तलाशने की कोशिश की ताकि इस साल का बजट वर्ष के अंत तक पारित हो सके।

इजरायल-हमास समझौते का नेपाल ने किया स्वागत, विपिन जोशी के रिहा होने की उम्मीद बढ़ी

काठमांडू। नेपाल सरकार ने इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। समझौते के तहत हमास ने 20 इजरायली बंधकों कमरिया करने की शर्त मान ली है। अब हमास के कब्जे से नेपाली नागरिक विपिन जोशी के रिहा होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावित मध्य पूर्व शांति योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए इजरायल और हमास के बीच हुआ समझौता स्वागत करने योग्य है। नेपाल ने इस समझौते के बाद नेपाली नागरिक बिपिन जोशी सहित सभी बंधकों को तत्काल रिहा करने का आह्वान किया है, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 से पकड़ रखा है। नेपाल सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे इस योजना को अपनी वास्तविक भावना से लागू करें, ताकि गाजा के लोगों को मानवीय सहायता का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और क्षेत्र और उससे आगे स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। नेपाल ने इस बहुप्रतीक्षित समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्किये की सराहना की है।

गाजा युद्धविराम समझौते की 'निगरानी' के लिए अमेरिका भेजेगा लगभग 200 सैनिक

वाशिंगटन। अमेरिका, इज़रायल और हमास के बीच गाजा युद्धविराम समझौते की 'निगरानी' के लिए इज़रायल में लगभग 200 सैनिक भेज रहा है। अमेरिकी मीडिया ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि टास्क फोर्स समझौते की'निगरानी, निरीक्षण और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उल्लंघन न हो'। अधिकारी के अनुसार, मिस्र, कतर और तुर्की सशस्त्र बलों के सदस्य अमेरिकी टीम में शामिल होंगे। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि टास्क फोर्स गाजा में नहीं होगी।

हमास कमांडर ने कैदियों की अदला-बदली को लेकर इजरायल के साथ मतभेद की चेतावनी दी

गाजा। हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद मर्दावी ने चेतावनी दी है कि कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को लेकर इजरायल के साथ उसके मौजूदा मतभेद वर्तमान में जारी मध्यस्थता प्रक्रिया को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। मर्दावी ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि नेतन्याहू युद्ध विराम समझौते को लागू होने से पहले ही इसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं तथा कैदियों की रिहाई की सूची से इनकार कर समझौते को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्दावी ने आरोप लगाया कि कैदियों के मुद्दे पर सहमति का अभाव, सैनिकों की वापसी, पुनर्निर्माण एवं गाजा पट्टी के अंदर और बाहर क्रॉसिंग को पुनः खोलने के संबंध में इजरायल की अविश्वसनीयता को उजागर करता है जबकि दोनों पक्ष अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्री पहल के पहले चरण पर सहमत होने में सक्षम हैं।

नेपाल की प्रधानमंत्री ने जेन जी की भावनाओं के पूरे सम्मान का दिया भरोसा

एजेंसी

काठमांडू। प्रधानमंत्री (पीएम) सुशीला कार्की ने जेन जी विद्रोह के एक महीना पूरा होने पर वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि जेन जी की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। यह वीडियो संदेश बीती देर रात जारी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और गृहमंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे युवाओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री कार्की ने देश के जेन जी समूह को यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जेन जी की भावनाओं का सम्मान करती है और उनकी मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जेन जी विद्रोह के दौरान मारे गए युवाओं को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री कार्की ने अपने संबोधन में

स्वीकार किया है कि पिछली सरकारें जेन जी की आवाज़ और चिंताओं पर ध्यान देने में विफल रही हैं। कार्की ने कहा है कि यह सरकार जेन जी की मांगों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री कार्की ने नेपाल के युवाओं द्वारा मांगे गए परिवर्तनों के लिए अपनी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, संयम और रचनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्की ने कहा, हम सभी को युवा पीढ़ी के नेतृत्व में क्रांति को स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ, हमारे युवा बहुत निराश हैं। दूसरी ओर, वे इस देश के प्रति प्यार रखते हैं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। पिछली सरकारें उनकी आवाज सुनने और उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहीं। इसके लिए हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार नेपाल के भविष्य को आकार देने में जेन-जी की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नया तंत्र स्थापित करेगी। हम नए नेपाल के निर्माण में जेन-जी को शामिल करने के लिए एक नई संरचना स्थापित कर रहे हैं, कार्की ने कहा। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री कार्की ने सभी से संयम बरतने और हिंसा के चक्र को तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा अब हमें इस दुखद अध्याय को बेहतर कल की नींव में बदलने के लिए आपसी सद्भावना और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

पाकिस्तानी सेना ने ओरकजई हमले में शामिल 30 आतंकी मारे

एजेंसी

रावलपिंडी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि सात अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओरकजई जिले में हुए हमले से जुड़े 30 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस हमले में दो अधिकारियों सहित 11 सैन्यकर्मी मारे गए थे। मीडिया शाखा ने कहा कि सुरक्षा बल इस जघन्य घटना में शामिल आतंकवादियों की तलाश में चप्पा-चप्पा छान रहे हैं। द न्यूज अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर ओरकजई जिले के जमाल माया क्षेत्र में

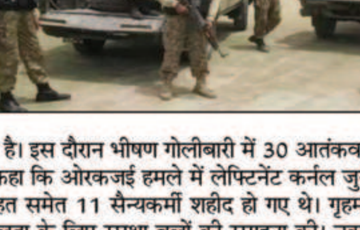

तलाशी अभियान शुरू किया है। इस दौरान भीषण गोलीबारी में 30 आतंकवादी मारे गए। आईएसपीआर ने कहा कि ओरकजई हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैय्यब राहत समेत 11 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। नकवी ने कहा, आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में शहीद सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

रिहा किए जाने वाले हमास के बंधकों की सूची में नेपाली नागरिक बिपिन जोशी का नाम नहीं, परिजन चिंतित

एजेंसी

काठमांडू। इजरायल और हमास के बीच हुए नए संघर्ष विराम समझौते के तहत सोमवार तक गाजा से 20 जीवित बंधकों की रिहा किया जाना है। रिहा किए जाने वाले इन बंधकों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है लेकिन उसमें नेपाली नागरिक बिपिन जोशी का नाम शामिल नहीं है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को दो साल के बाद संघर्ष विराम के पहले चरण में रिहा किया जा रहा है लेकिन नेपाली नागरिक का नाम उसमें शामिल नहीं है जिससे उसके परिजन बेहद चिंतित हैं। हमास और उसके सहयोगियों ने हमले के दौरान इज़राइल से 251 लोगों का अपहरण किया था और उन्हें गाजा ले गए थे। इनमें से 47 लोगों के अभी भी हमास के कब्जे में रहने की बात बताई गई है। पहले चरण में 20 लोगों की रिहाई सोमवार तक होने की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से की गई है। इज़राइल पहले ही बंधकों में से 26 को मृत घोषित कर चुका है। जिन लोगों की स्थिति अज्ञात है उनमें

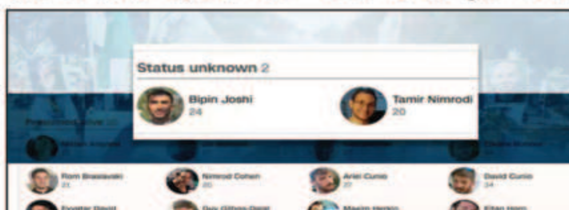

इजरायली सैनिक तामीर निमरोदी और नेपाली छात्र बिपिन जोशी शामिल हैं। नेपाल के जोशी का दक्षिणी इज़राइल के एलुमिन किबुत्ज़ से अपहरण कर लिया गया था। उनके परिवार ने हाल ही में पुष्टि की कि इजरायली बलों ने गाजा से एक वीडियो बरामद किया है जिसमें उन्हें जीवित दिखाया गया है, माना जाता है कि फुटेज नवंबर 2023 में फिल्माया गया था। इजरायली मीडिया ने बताया कि वर्तमान संघर्ष विराम प्रस्ताव के तहत, 20 जीवित बंधकों और 28 मृतक के अवशेषों को इज़राइल को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि हमास को सभी मृतकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। बिपिन जोशी के मामले ने नेपाल और इज़राइल में विशेष ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह एकमात्र ज्ञात नेपाली बंधक है जिनके बारे में अभी भी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है।

राजनाथ सिंह ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख बेस का अवलोकन किया

एजेंसी

कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया)। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के आखिरी दिन आज सुबह सिडनी पहुंचे। सिंह ने यहां स्थित एचएमएएस कुत्ताबुल का दौरा किया। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का प्रमुख बेस है। यह प्रमुख बेस पॉट्स पॉइंट पर स्थित है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा भी किया। उन्होंने फ्लीट बेस ईस्ट के दौरे में ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी हासिल की। इससे पहले सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के कुछ फोटो और उनकी विवरण साझा किया। एक्स पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, सिंह ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह युद्ध स्मारक दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा में उनके साहस और बलिदान

का प्रतीक है। सिंह ने भारतीय सैनिकों की स्मृति को नमन किया। यह ऐसे योद्धा हैं, जिन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथियों के साथ सुदूर देशों में वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। इसके अलावा सिंह ने राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। सिंह ने एक्स पर लिखा,' शानदार मुलाकात। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत के साथ अपने गहरे जुड़ाव को बड़े प्यार से याद किया। मुझे विश्वास है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध और भी गहरे और मज़बूत होते जाएंगे।

ट्रंप ने कहा-इजराइल और हमास ने मानी बात, गाजा में शांति को तैयार, दोनों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ देर पहले कहा कि इजराइल और हमास उनकी गाजा शांति योजना को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों ने उनकी 20 सूत्री इस योजना पर सहमति जताई है। युद्धविराम के प्रथम चरण के लिए दोनों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनुमान है कि बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि मिस्र के शर्म अल-शेख शहर में इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए परोक्ष वार्ता चल रही है। हमास ने बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला-बदली की सूची सौंप दी है।

सीएनएन न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह घोषणा करने से पहले स्टेट डाइनिंग रूम से निकलने के बाद से ओवल ऑफिस में फोन पर बातचीत की। इससे लगभग एक घंटे पहले स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर से बात की। कुछ देरबाद

इजराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता की प्रगति का विवरण अपने ट्रुथ सोशल पर साझा किया। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अमेरिका का अनुमान है कि बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू होगी। इस अधिकारी ने कहा कि अब इजराइली कैबिनेट के समक्ष इस समझौते के प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके बाद युद्धविराम योजना पर अमल शुरू हो जाएगा।

इस बीच इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें इजराइली संसद नेसेट को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, ट्रंप ने नेतन्याहू को उनके नेतृत्व और कार्यों के लिए बधाई दी। उधर, युद्धविराम संबंधी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। बंधकों के परिवारों ने खुशी जताई है। बंधक गली और जिव बर्मन के भाई लिरन बर्मन ने समझौते की घोषणा के तुरंत बाद एक्स पर कहा कि वह सचमुच बहुत खुश है। वह अपने प्रियजनों से जल्द से जल्द मिलना चाहता है। इजराइली रक्षा बल के सैनिक इतेय चेन (जिनका शव हमास के पास है) के पिता रूबी चेन ने एक पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी वार्ता दल के अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया है।

पुतिन ने अजरबैजान विमान दुर्घटना में पहली बार मानी गलती

एजेंसी

मास्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस के विमान हादसे में पहली बार रूस की भूमिका को स्वीकार किया है। पुतिन ने कहा कि रूस ने घटना की सुबह यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की थीं और वे विमान से कुछ मीटर की दूरी पर फट गए। पुतिन ने ताजिकिस्तान में दूसरे रूस-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात के दौरान यह बात कही। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने अपने समकक्ष को बताया कि यह घटना तब हुई जब यूक्रेनी ड्रोनों पर नज़र रख रही रूसी मिसाइलें नागरिक विमान से कुछ ही मीटर की दूरी पर फट गईं। पुतिन ने कहा, रूस अपनी सीमा पार करने वाले तीन यूक्रेनी ड्रोनों पर नज़र रख रहा था। रूस द्वारा दागी गई दो वायु-रक्षा मिसाइलें सीधे विमान से नहीं टकराईं बल्कि वे कुछ मीटर की दूरी पर फट गईं। विमान संभवतः मिसाइलों से नहीं, बल्कि उसके टुकड़ों से क्षतिग्रस्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर 2024 को इस विमान ने अज़रबैजान की राजधानी बाकू से रूस के ग्रोज़्नी के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 62 यात्री, दो पायलट और तीन केबिन क्रू सदस्य सहित 67 लोग सवार थे। यह कज़ाकिस्तान के अकातु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 35 यात्री, दोनों पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मारा गया था। घटना के तीन दिन बाद 28 दिसंबर को पुतिन ने अलीयेव से फ़ोन पर बात की और घटना के लिए माफ़ी मांगी। उस समय उन्होंने कहा था कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियां यूक्रेनी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय थीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं किया था कि विमान को गिराने के लिए रूसी मिसाइलें ज़िम्मेदार थीं।

बलोचिस्तान में सात अक्टूबर को बलघाटर हमले में पाकिस्तानी सेना के 14 जवान मारे गए'-बीएलएफ के विस्तृत बयान में दावा

एजेंसी

क्वेटा (बलूचिस्तान)। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने सात अक्टूबर को बलघाटर में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर हमले पर विस्तृत बयान जारी किया है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर घोरम बलोच ने कहा कि लड़ाकों ने बलघाटर में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया। 14 सैन्यकर्मियों को मार डाला और चार को घायल कर दिया। उनके हथियार और अन्य सैन्य उपकरण छीन लिए। आजादी के इस आंदोलन में उसकी कुर्बान यूनिट के प्रमुख अब्दुल्ला दियार उर्फ ??सोगहत की जान चली गई। द बलोचिस्तान पोस्ट (पश्तो भाषा) की रिपोर्ट के अनुसार, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर घोरम बलोच ने विस्तृत बयान नौ अगस्त

को जारी किया। प्रवक्ता ने बताया कि सात अक्टूबर को शाम 5:00 बजे फ्रंट ने बलघाटर क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया। भारी हथियारों से किया गया एक बड़ा हमला तीन घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा। लड़ाकों ने चौकी पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और हथियार व अन्य सैन्य उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। इस संगठित हमले में पाकिस्तान सेना के 14 सैनिक मारे गए और चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि चौकी पर कब्जे के बाद सेना के त्वरित प्रतिक्रिया बल के चार वाहनों को पंजगुर से हमला स्थल पर बलों की मदद के लिए भेजा गया। लड़ाकों ने त्वरित प्रतिक्रिया बल पर घात लगाकर हमला कर दिया और सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाकों ने दो क्वाडकॉप्टर और एक ड्रोन कैमरा भी मार गिराया गया। प्रवक्ता ने कहा कि बलोचिस्तान में बलात कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना मनोवैज्ञानिक रूप से इतनी पराजित हो चुकी है कि वह अपने मृत सैनिकों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

ट्रम्प ने ईरान पर हुए हमलों को बताया गाजा शांति समझौते का निर्णायक कारक

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले गाजा संघर्षविराम समझौते को संभव बनाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। उन्होंने कहा कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित कर दिया और क्षेत्र में शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा, 'मेरा मानना है कि ईरान पर हमला बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो उनके पास अब तक कई परमाणु हथियार होते। तब चाहे हम कोई भी समझौता करते, उस पर एक काला साया बना रहता और उसकी अहमियत नहीं रहती।' रिपोर्टों के अनुसार, इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद उसी महीने अमेरिका ने भी ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर निशाना साधा था,

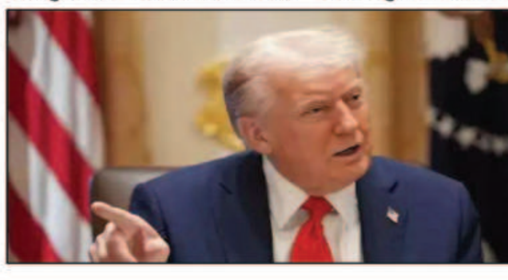

जिससे वे 'गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त' हो गए। ट्रम्प ने आगे कहा, 'अब ईरान अलग है, उन्होंने हमें सूचित किया है कि वे इस शांति समझौते के पूरी तरह पक्ष में हैं। वे इसे एक अच्छी पहल मानते हैं, और हम उनके साथ मिलकर आगे काम करेंगे।÷ उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने देश का पुनर्निर्माण करे, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास परमाणु हथियार न हों। ट्रम्प के मुताबिक, ईरान पर हुए हमले ने 'क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया' और अब मध्य पूर्व में 'शांति और सहयोग के नए युग' की संभावना बढ़ गई है।

उत्तरी अफगानिस्तान में सोने की खदान ढहने से दो खनिकों की मौत

एजेंसी

काबुल। उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में बुधवार को सोने की एक खदान की सुरंग ढह जाने से दो स्वर्ण खनिकों की मौत हो गयी। यह जानकारी प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता

एहसानुल्लाह कामगर ने दी।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि कल अरघांच खाह जिले में खनिक सोने की खदान से सोना निकालने का कार्य कर रहे थे तभी सुरंग धंस गई जिससे दो खनिकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। इससे पहले, जुलाई में बदख्शां के रघिस्तान जिले में इसी प्रकार की घटना में दो स्वर्ण खनिकों की मौत हो गई थी तथा एक अन्य घायल हो गया था। उल्लेखनीय है कि गैर मापदंड वाले खनन, आधुनिक मशीनरी के आभाव, अकुशल श्रमिकों द्वारा अवैध खनन तथा सुरक्षा सावधानियों की अनदेखी के कारण अफगानिस्तान में गरीब श्रमिकों की प्रायः मौत हो जाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टकराने वालीं न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल जेम्स के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा

एजेंसी

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर राजनीतिक विरोधी न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स पर एक बंधक धोखाधड़ी मामले में अभियोग लगाया गया। ट्रंप ने संघीय न्याय विभाग से इस मामले को सामने लाने का आग्रह किया था। लेटिटिया जेम्स डेमोक्रेट हैं। वह ट्रंप पर मुकदमा दायर कर उनसे लोहा ले चुकी हैं। जेम्स खुलेआम आरोप लगाती रही हैं कि ट्रंप ने अपना व्यापारिक साम्राज्य झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया है। एबीसी न्यूज चैनल पर ट्रंप और जेम्स के विवाद पर प्रसारित रिपोर्ट में गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जेम्स ने उन पर 2020 में नॉरफॉक (वर्जीनिया) में एक घर खरीदने के संबंध में बैंक धोखाधड़ी और एक वित्तीय संस्थान को झूठे बयान देने का आरोप लगाया था। वर्जीनिया के पूर्वी जिले की शीर्ष संघीय अभियोजक लिंडसे हॉलिगन ने व्यक्तिगत रूप से ग्रैंड जूरी के सामने जेम्स के खिलाफ मामला पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार,ट्रंप और जेम्स के

बीच टकराव बढ़ गया है। जेम्स ने 2018 में अटॉर्नी जनरल पद के लिए अपने अभियान में ट्रंप और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की थी। कुछ समय बाद डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने के बाद जेम्स ने कहा था, मैं इस नाजायज राष्ट्रपति को चुनौती देने से कभी नहीं डरूंगी। अटॉर्नी जनरल के रूप में ट्रम्प के रियल एस्टेट सौदों में हुई हेराफेरी को सामने लाऊंगी। हर सौदे में हर मोड़ पर सच्चाई की मांग करूंगी। ट्रंप ने 2019 में ट्वीट (अब एक्स) किया था, न्यूयॉर्क में रहना बहुत कठिन और महंगा है। यहां के गवर्नर एंड्रयू कुओमो अपनी अटॉर्नी जनरल (लेटिटिया जेम्स) को अपने स्वार्थ के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे हर चीज पर मुकदमा करते हैं। वह हमेशा मुझे फंसाने के लिए किसी न किसी अपराध की तलाश में रहते हैं। इस पर जेम्स ने सोशल मीडिया साइट पर ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कोई गलती न करें। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति भी नहीं। पुनश्चः मेरा नाम लेटिटिया जेम्स है। आप मुझे टिश कह सकते हैं।। इसके बाद मार्च 2019 में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कथित धोखाधड़ी की जांच शुरू की। जेम्स के कार्यालय ने उन आरोपों की जांच की कि जिनमें कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व राष्ट्रपति की कुल संपत्ति को अरबों डॉलर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और झूठे और भ्रामक वित्तीय विवरणों के जरिए ऋणदाताओं और अन्य लोगों को धोखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बिजनेस को देख रहे अधिकारियों ने इसकी परवाह नहीं की। यह जांच लगभग तीन साल चली। इन सबने इस अवधि में जारी किए गए समन और अन्य अदालती आदेशों का पालन करने में कोई सहयोग नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति ने अगस्त 2022 में गवाही दी। इसके एक माह बाद जेम्स ने ट्रंप, उनके तीन वयस्क बच्चों और ट्रंप ऑर्गेनाइज़ेशन, दो अधिकारियों एलन वीसेलबर्ग और जेफ मैककोनी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया।

कैट ने करवा चौथ पर देशभर में 25 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का जताया अनुमान

एजेंसी

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने करवा चौथ पर देश में 25 हजार करोड़ रुपये के व्यापार होने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक उत्सव का माहौल बना रहता है, जो दिवाली तक चलता है। करवा चौथ हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग में नहीं, बल्कि समानता और परस्पर आदर में निहित है। जब पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे की खुशहाली के लिए व्रत रखते हैं, तभी यह पर्व अपने वास्तविक और श्रेष्ठ स्वरूप में मनाया जा सकता है। चांदनी चौक से सांसद तथा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने देशभर के लोगों खास तौर पर व्यापारियों से अपील की है कि वो भी अपनी पत्नी के सम्मान में करवा चौथ का व्रत रखें। उन्होंने कहा कि वे खुद पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से करवा चौथ का व्रत रखते हैं। उन?होंने कहा कि जिस प्रकार महिलाएं अपने पतियों के दीर्घ जीवन के लिए उपवास रखती हैं, उसी प्रकार पुरुषों को भी अपनी पत्नियों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली के लिए व्रत रखना चाहिए। कैट महामंत्री ने कहा कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ जैसे बड़े त्यौहार को देखते हुए दिल्ली एवं देश के बाजारों में बड़े स्तर पर व्यापारियों ने तैयारियां की हैं।

शिरीष चंद्र मुर्मू ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। शिरीष चंद्र मुर्मू ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल लिया। मुर्मू विनियमन एवं प्रवर्तन सहित चार विभागों का कार्यभार संभालेंगे। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। मुर्मू इस पहले केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे। वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि संजय कुमार हंसदा को तीन मार्च, 2025 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिरीष चंद्र मुर्मू 1991 में रिजर्व बैंक में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने पूर्व में बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक के निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है, साथ ही ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है।

स्पेक्ट्रम की कीमतें तय होने के बाद देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होंगी : सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से स्पेक्ट्रम की कीमतें तय होने के बाद देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होंगी। इसके पहले कंपनियों को भी अपनी योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दो कंपनियों को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि एक अन्य को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2025) में पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि यह कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी अपनी क्रियान्वयन रणनीति लागू कर पाती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक मुद्दा यह है कि ट्राई को अभी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना है। यह लंबित हिस्सा है और नियामक इसे पूरा करेगा। वोडाफोन आइडिया को राहत दिए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कर्ज में डूबी इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की किसी भी योजना से इनकार किया। इससे पहले दूरसंचार मंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 के दूसरे दिन की शुरुआत भारत के दूरसंचार दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए हितधारकों के साथ नेतृत्व संवाद के साथ किया।

केनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च, 13 तक कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड कंपनी केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का 1,326.13 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 13 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 4,98,54,357 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में कोई भी नया शेयर जारी नहीं हो रहा है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 253 रुपये से लेकर 266 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 56 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,896 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले बुधवार को केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से 397.84 करोड़ रुपये जुटाए। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 53.26 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है।

सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी, नए शिखर पर सोना और चांदी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला आज भी जारी है। ये दोनों चमकीली धातुएं आज एक बार फिर मजबूती के नए शिखर पर पहुंची हुई हैं। आज के कारोबार में सोना 200 रुपये से लेकर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। इसी तरह चांदी 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक उछल कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। कीमत में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,24,160 रुपये से लेकर 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,13,810 रुपये से लेकर 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं, चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,67,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,24,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर

पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,24,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,13,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

स्पाइसजेट एयरलाइन ने अपने बेड़े में तीन और विमान जोड़े

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में सस्ती विमानन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने अपने परिचालन बेड़े में तीन नए विमान जोड़े हैं। इनमें एक एयरबस ए340 चौड़ा आकार और दो बोइंग 737 विमान शामिल हैं। एयरलाइन के बेड़े का विस्तार होने से छुट्टियों के मौसम में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग पूरी हो सकेगी। स्पाइसजेट ने शुक्रवार को 'एक्स' पोस्ट पर बताया कि उसे तीन नए विमान मिले हैं, जिनमें एक एयरबस ए340 वाइड-बॉडी और दो बोइंग 737 हैं।एयरलाइन ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के बीच कुल 20 विमान उसके परिचालन बेड़े में शामिल होंगे। इनका संचालन डैम्प लीज मॉडल के तहत किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने लीज की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एयरलाइन ने बताया कि ये नए विमान 10 और 11 अक्टूबर के बीच परिचालन में आ जाएंगे। इसके साथ ही एयरलाइन दिसंबर के मध्य तक चार विमानों को भी उतार देगी, जिससे उसकी क्षमता और बढ़ेगी। एयरलाइन ने कहा कि उसके बेड़े का विस्तार इस छुट्टियों के मौसम में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। कंपनी ने कहा कि हम गति पकड़ रहे हैं। शीतकालीन योजना प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करके हमारे मेहमानों के लिए नए अवसर खोलेगी। हम विवेकपूर्ण तरीके से क्षमता वृद्धि, समय पर प्रदर्शन में सुधार और अपने ग्राहकों व भागीदारों को मूल्य प्रदान करना जारी रखेंगे।

ईरानी तेल खरीद पर अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी समेत 100 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार में सहयोग देने के आरोप में करीब 100 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें चीन की एक स्वतंत्र रिफाइनरी और तेल टर्मिनल भी शामिल हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा 09 अक्टूबर को की गई। अमेरिकी वित्त विभाग ने चीन की शानडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी को प्रतिबंधित किया है। यह शानडोंग प्रांत में स्थित एक स्वतंत्र रिफाइनरी है, जिसने 2023 से अब तक लाखों बैरल ईरानी तेल खरीदे हैं। इसके अलावा, रिजाओ शिहुआ क्रूड ऑयल टर्मिनल कंपनी को भी निशाने पर लिया गया है, जो लानशान पोर्ट पर टर्मिनल संचालित करती है। विभाग के अनुसार, इस टर्मिनल ने ईरान के शैडो फ्लीट के दर्जनभर से अधिक जहाजों से तेल उतारा है, जिनमें Kongm, Big Mag और Voy जैसे टैंकर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान का तेल नेटवर्क उसकी परमाणु और मिसाइल योजनाओं को

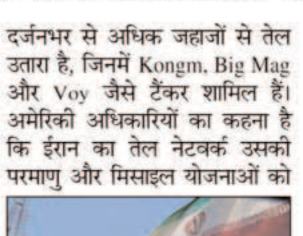

वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वह मध्य पूर्व में उग्रवादी समूहों को समर्थन देता है। हालांकि, ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, ÷वित्त विभाग ईरान की ऊर्जा निर्यात प्रणाली के प्रमुख हिस्सों को ध्वस्त करके उसकी नकदी प्रवाह को कमजोर कर रहा है।÷ यह चीन स्थित रिफाइनरियों पर चौथी कार्रवाई है, जिन पर ईरानी तेल खरीद जारी रखने का आरोप है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि पहली बार किसी चीन-आधारित टर्मिनल, जियांगयिन फॉरएवरसन केमिकल लॉजिस्टिक्स, को भी ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्धविराम और बंधक सौदा हुआ है, जो यदि पूरी तरह लागू होता है तो यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है, जिससे ईरान, यमन और लेबनान जैसे देशों को शामिल करने वाला क्षेत्रीय संघर्ष शांत हो सकता है। चीन के वॉशिंगटन स्थित दूतावास और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

वीवर्क इंडिया की स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री, घाटे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के लिमिटेड शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 648 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 1.50 रुपये डिस्काउंट के साथ 646.50 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 2 रुपये प्रीमियम के साथ 650 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयरों के भाव में और गिरावट आ गई। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 633.85 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के लिमिटेड का 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ 3 से 7 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.15 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.79 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.23 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 0.62 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.87 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 4,62,96,296 शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 146.81 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में घट कर 135.77 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इसके अगले साल 2024-25 में कंपनी घाटे से उबरने में सफल रही। इस वित्त वर्ष में कंपनी को 128.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस दौरान कंपनी का राजस्व 19 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 2,024 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 485.61 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 625.83 करोड़ रुपये हो गया। इसे अगले साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज घट कर 310.22 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई ने चारों डिप्टी गवर्नरों के विभागों में किया फेरबदल, नई व्यवस्था लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चार डिप्टी गवर्नरों के विभागों में फेरबदल किया है। आरबीआई ने अपने 32 विभागों को उनके बीच बांट भी दिया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि एम राजेश्वर राव के सेवानिवृत्त होने के बाद आज डिप्टी गवर्नर का पदभार संभालने वाले शिरीष चंद्र मुर्मू संचार, सरकारी और बैंक खाते, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का कार्यभार संभालेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक शिरीष चंद्र मुर्मू की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने और अन्य तीन डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन और पूनम गुप्ता हैं। इनके 09 अक्टूबर, 2025 से उप-गवर्नरों के बीच विभागों का वितरण निम्नलिखित होगा। आरबीआई ने वरियता के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया है।

इसमें पहले नंबर के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर के पास कॉर्पोरेट रणनीति एवं बजट विभाग, मुद्रा प्रबंधन विभाग, बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, फिनटेक विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और सचिव विभाग है। रिजर्व बैंक के दूसरे नंबर पर डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन के पास केंद्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, पर्यवेक्षण विभाग, निक्षेप बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, निरीक्षण विभाग, विधि विभाग, परिसर विभाग और सूचना का अधिकार (आरआईए) प्रभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आरबीआई ने तीसरे नंबर पर डिप्टी गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता को आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग, वित्तीय बाजार संचालन विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग और मौद्रिक नीति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को संचार विभाग, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, विनियमन विभाग और प्रवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी है।

टीसीएस का सितंबर तिमाही में मुनाफा 1.4 फीसदी बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर को समाप्त (जुलाई-सितंबर) तिमाही में टीसीएस का एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39 फीसदी बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। टीसीएस ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में उसका परिचालन राजस्व 2.39 फीसदी बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 64,259 करोड़ रुपये था। टाटा समूह की इस कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के साथ ही जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में कंपनी के लाभ में 5.3 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि उसके राजस्व में 3.7 फीसदी की

वृद्धि हुई है। टीसीएस ने कंपनी के एक रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। टीसीएस की वित्तीय परिणामों की घोषणा आज शेयर बाजार बंद होने के बाद की गई है।

सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है। अब पीएलआई योजना आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया गया है। इसका उद्देश्य उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। कपड़ा मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सिंथेटिक या कृत्रिम रूप से बनाए गए रेशों से बने परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। मंत्रालय ने उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना का आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया है। मंत्रालय ने कहा कि? ये महत्वपूर्ण संशोधन वस?त्र उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने, व्यापार सुगमता बढ़ाने, इस क्षेत्र में नए निवेश प्रोत्साहित करने और विकास को गति देने के लिए किए गए हैं। यह बदलाव रोज़गार को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में भारत की पहुंच व्यापक बनाने के सरकार के ध्यान को रेखांकित करते हैं। योजना के संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।

पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधनः

पात्र उत्पादों का विस्तारः मैन मेड फाइबर परिधान के लिए वैश्विक व?यापार सुगमता मानक संबंधी 8 नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर

कोड और मैन मेड फाइबर कपड़े (फैब्रिक्स) के लिए 9 नए एचएसएन कोड शामिल करना।

नई कंपनियां स्थापित करने से छूट÷ आवेदक अब मौजूदा कंपनियों के अंतर्गत परियोजना इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। निवेश की न्यूनतम सीमा में कमी की गईः दिनांक 01 अगस्त, 2025 से सभी नए आवेदकों के लिए योजना के भाग-1 श्रेणी में न्यूनतम निवेश 300 करोड़ रुपये से घटाकर 150 करोड़ रुपये और भाग-2 श्रेणी में 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये किया गया। प्रोत्साहन के लिए वृद्धिशील टर्नओवर मानदंड में कमी की गई, इसे पहले के 25 फीसदी से घटाकर इसे 10 फीसदी किया गया है। चालू वित?त वर्ष 2025-26 से आवेदकों को अब प्रोत्साहन प्राप?त करने की अर्हता हेतु पिछले वित?त वर्ष की तुलना में न्यूनतम 10 फीसदी वृद्धिशील टर्नओवर प्रदर्शित करना होगा (दूसरे वर्ष से)। उपरोक्त संशोधनों से प्रवेश संबंधी बाधाएं और वित्तीय सीमाएं काफी कम हो जाएंगी, जिससे क्रियान्वयन तेजी से संभव हो सकेगा। आवेदन समय-सीमा विस्तारित÷ वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, पीएलआई योजना आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया है। इच्छुक कंपनियों से आग्रह किया जाता है कि वे संशोधित ढांचे और बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाकर आवेदन करें ।

भारत की तकनीक और एआई नवाचार लाखों लोगों के जीवन में ला रहे हैं बदलाव : डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि यूपीआई से लेकर ओएनडीसी तक भारत के नवाचार सिर्फ प्रौद्योगिकी के लिए तकनीक पर आधारित नहीं हैं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने पर केंद्रित हैं।

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन को नया आकार दे रही हैं। डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा, भारत के नवाचार केवल प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं हैं, वे जीवन बदलने के बारे में हैं। उन?होंने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन को नया आकार दे रही हैं। मंत्री ने बताया कि यूपीआई ने निर्बाध भुगतान को सार्वभौमिक बना दिया है, ओएनडीसी ने छोटे विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स के अवसर खोले हैं और एआई-संचालित अलर्ट सिस्टम ने 2024 की केरल बाढ़ के दौरान 500,000 से अधिक लोगों की जान बचाई। उन्होंने दूरसंचार विभाग के एआई-संचालित धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का हवाला देते हुए बताया कि, जिसने 48 लाख घोटालों को रोका और 140 करोड़ रुपये की हानि को टाल दिया। उन्होंने कहा कि ये नवाचार दर्शाते हैं कि भारत अपने लोगों को सशक्त बनाने, उनको सुरक्षा देने और उनको ऊपर उठाने के लिए एआई का उपयोग कैसे करता है।

डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, एयरलाइन आदेश को देगी चुनौती

एजेंसी

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। कंपनी इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग बताया कि 26 सितंबर को डीजीसीए से जुर्माने के संबंध में नोटिस मिला है।

एयरलाइन पर पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए एयरलाइन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना श्रेणी ष्ट एयरपोर्ट पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग करने में कथित विफलता के लिए लगाया गया है। विमानन कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि डीजीसीए के इस आदेश को उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर विचार किया जा रहा है। एयरलाइन ने कहा आंतरिक संप्रेषण संचार में देरी के कारण जुर्माने की जानकारी देने में इतना समय लग गया। कंपनी ने कहा कि डीजीसीए के आदेश के कारण उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आमतौर पर श्रेणी 'सी' के हवाई अड्डों की पहुंच और परिचालन स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं।

मीडियाटेक ने डाइमेंशन 9500 चिपसेट के साथ एआई विजन का अनावरण किया

एजेंसी

नई दिल्ली। विश्व की अग्रणी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक ने राजधानी नई दिल्ली के यशोभूमि में 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025' में अपने टेक्नोलॉजी रूपरेखा को अत्याधुनिक ढंग से मजबूत करते हुए एआई के भविष्य को आकार प्रदान करने के लिए अपना विजन पेश किया। हर वर्ष दो अरब से अधिक कनेक्टेड डिवाइसेस को ताकत दे रही मीडियाटेक ने विस्तृत एन2पी प्रोसेस पर अगली पीढ़ी का अग्रणी एसओसी विकसित करने के लिए टीएसएमसी के साथ गठबंधन की भी घोषणा की। अगले वर्ष बड़ी मात्रा में इसके उत्पादन शुरू होने की संभावना है। 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025' में आयोजित मीडिया के साथ अपनी विशेष बातचीत में मीडियाटेक ने अपना नवीनतम अग्रणी चिपसेट दि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 पेश किया जिसे अगली पीढ़ी के 5जी स्मार्टफोन को सुपरचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट उद्योग के अग्रणी ऑन-डिवाइस एआई, कंसोल-ग्रेड गेमिंग और बेजोड़ पावर दक्षता का मेल कराती है जिससे मोबाइल का निष्पादन नए सिरे से परिभाषित होता है। मीडियाटेक ने अत्याधुनिक एआई और गेमिंग प्रदर्शन जैसे इमेज-टु-इमेज स्टाइल बातचीत, 4के रिजोल्यूशन टेक्स्ट-टु-इमेज जेनरेशन के जरिए मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 चिपसेट की पूर्ण क्षमताओं को रेखांकित किया और मेगा लाइट व नैनाइट जैसी अनरीयल इंजन टेक्नोलॉजीज के लिए मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 के सपोर्ट को प्रदर्शित किया जिससे कंसोल ग्रेड के रीयल टाइम विजुअल्स मिलते हैं और गतिशील लाइटिंग के साथ मोबाइल डिवाइस पर एएए गुणवत्ता के विवरण मिलते हैं। इस सत्र में ओईएम साझीदारों जैसे वीवो, टेक्नो, ओप्पो, सैमसंग और लावा ने प्रतिभाग किया जहां ओप्पो इंडिया के पीआर एवं कम्युनिकेशंस प्रमुख गोल्डी पटनायक ने ओप्पो की आगामी फाइंड एक्स9 सीरीज पर मुख्य व्याख्यान दिया। यह सीरीज डायमेन्सिटी 9500 एसओसी से युक्त होगी। मीडियाटेक इंडिया के प्रबंध निदेशक अंकु जैन ने कहा, एआई के दैनिक जीवन का आंतरिक हिस्सा बनने के साथ उपभोक्ता ऐसे डिवाइसेस की उम्मीद करते हैं जिसमें अधिक सूझबूझ, गति और व्यक्तिगत क्षमता हो और साथ ही वे ऊर्जा दक्षता भी बनाए रखें। हमारा मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 ऑन-डिवाइस एआई पर सफलता प्रदान करता है और साथ ही इसका निष्पादन जबरदस्त है।

इसके अलावा, यह पूर्ण प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है जिसे हमारे ओईएम दुनियाभर में अपने यूज़र्स को उपलब्ध करा सकते हैं। आईएमसी 2025 की थीम इन्नोवेट टु ट्रांसफॉर्म की तर्ज पर मीडियाटेक ने कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया उत्पादों और टेक्नोलॉजीज में अपना लंबा और गहरा अनुभव प्रदर्शित किया। मीडियाटेक ने विश्व के अग्रणी ब्रांडों की ओर से विभिन्न वर्टिकल्स में मीडियाटेक से शक्ति प्राप्त डिवाइसेस में अपने नवीनतम टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को भी प्रदर्शित किया। इनमें मीडियाटेक कॉम्पैनियो 520 से ताकत प्राप्त एचपी जी1एम क्रोमबुक, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9300प्लस से युक्त वीवो एक्स200 और मीडियाटेक से ताकत प्राप्त लुमियो आर्क 5 प्रोजेक्टर शामिल थे। इसके अलावा, मीडियाटेक ने प्रमुख परिचर्चाओं के जरिए आईएमसी 2025 में चिंतन में भी योगदान किया। इनमें कारोबार विकास एवं बिक्री प्रमुख राघवन संपत के साथ फ्यूचर गैजेट्सः डिजाइन्ड एंड बिल्ट फ्रॉम इंडिया विषय पर आयोजित सत्र शामिल है जिसमें उन्होंने यह बात रेखांकित की कि कैसे अगली पीढ़ी के चिपसेट स्मार्टर, अधिक तेज और तल्लीनता भरे ग्राहक अनुभव को ताकत प्रदान कर रहे हैं। वहीं, 'चार्टिंग इंडियाज टेलीकॉम विजनः ए लीडरशिप डायलॉग' विषय पर आयोजित परिचर्चा में अंकु जैन ने 5जी की तैनाती, दूरसंचार नेटवर्कों और एडवांस्ड एज कंप्यूटिंग में एआई के एकीकरण के लिए रणनीतियों की संभावना तलाशी।

मालती चाहर ने बदला गेम! रोटी पर हुई जंग, शाहबाज ने फरहाना को बनाया 'भूतनी'

'बिग बॉस 19' के घर में दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने आते ही पूरे गेम का नक्शा बदल दिया है. सलमान खान के इस शो को बाहर से देखकर आईं मालती कंटेस्टेंट्स के समीकरण को बखूबी समझती हैं और अपने तेवर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. उनकी एंट्री के बाद घरवालों के बीच हो रही खींचतान और गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है.बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में दिन की शुरुआत हमेशा की तरह किचन के झगड़े से हुई. भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर खाना नहीं बनाएंगी, जिससे किचन में बड़ा बवाल हो गया. घर के बिगड़े हालात देख अभिषेक ने मोर्चा संभाला और हिम्मत दिखाते हुए कहा कि अगर आप लोग साथ दें, तो वो खाना बना सकते हैं.

गौरव से टकराईं मालती

मालती ने किचन में रोटी बनाने में दिक्कत होने पर सदस्यों से मदद मांगी, लेकिन नेहल ने मना कर दिया और नीलम पहले ही साइड हो चुकी थीं. जब गौरव ने रोटी के आकार पर मालती से कुछ कहा, तब मालती ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप मत बोलिए गौरव जी, या तो आप ही कर लीजिए. इस पर गौरव ने जवाब दिया कि फ़ूड टीम में होने के नाते उन्हें बोलने का पूरा हक है. इस 'रोटी' विवाद की गॉसिप नीलम ने तुरंत अमाल और जीशान को बताई. अमाल ने मालती के खेल को समझते हुए कहा, अच्छा खिलाड़ी आया है.

मालती बनाम तान्या

मालती चाहर घर में आते ही पुराने मुद्दे उठा रही हैं, खासकर तान्या मित्तल से जुड़े. उनके इस रवैये से घर के कई सदस्य अब उन्हें नापसंद करने लगे हैं. नॉमिनेशन टास्क के दौरान तान्या इमोशनल होकर रो पड़ीं, जिससे मालती और तान्या के बीच का रिश्ता और खराब होता नजर आ रहा है. तान्या जीशान कादरी को अपना भाई मानती हैं, उन्हें मालती से बढ़ती नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. तान्या और नीलम लगातार मालती को लेकर चुगली कर रही हैं. तान्या ने नीलम से कहा कि मालती की वजह से सब उनसे दूर हो रहे हैं.

मालती, फरहाना और नेहल का 'नया ग्रुप' बना

वैसे तो अब तक बिग बॉस का घर दो गुटों में बंट चुका था. लेकिन अब फरहाना, मालती और नेहल ने आपस में मिलकर अपना एक नया ग्रुप बना लिया है. उन्होंने अपनी खूबियों पर चर्चा की और मालती ने कन्फर्म किया कि उनका ग्रुप तो पहले ही बन चुका है.

राशन टास्क में मालती बनीं पाम रीडर

बिग बॉस ने घरवालों को राशन कमाने के लिए एक टास्क दिया, जिसमें उन्हें कुछ फिगर्स बनाने थे. इस दौरान मालती ने पाम रीडर बनकर मजेदार भविष्यवाणी की. उन्होंने तान्या और नीलम का हाथ देखकर कहा, नीलम इतना टाइम इन्वेस्ट करती है तान्या को सुनने में. घरवालों ने मिलकर टास्क का 80% हिस्सा सफलतापूर्वक जीत लिया.

अब 33 साल छोटी एक्ट्रेस संग धमाल मचाएंगे सनी देओल, अगली बड़ी फिल्म का वीडियो LEAK, कब होगी रिलीज?

सनी देओल के साथ कौन?

अगले 2 साल जितना दूसरे एक्टर्स के लिए अहम हैं, उतने ही सनी देओल के लिए भी हैं. क्योंकि एक्टर के खाते में इस वक्त कई बड़ी फिल्में हैं, जिनका वो काम कर रहे हैं. काफी समय पहले ही सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' का काम कंप्लीट कर लिया था. फिर जानकारी मिली की रणबीर कपूर की 'रामायण' का भी शूट कर चुके हैं. उन्होंने एक फिल्म के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ भी हाथ मिलाया है. साथ ही राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 का भी जल्द काम खत्म करना है. लेकिन इसी बीच एक और बड़ी फिल्म के सेट से उनकी तस्वीर और वीडियो लीक हो गए हैं. जो लंबे वक्त से अटकी हुई थी.

इस वक्त ङ्क पर सनी देओल की भर-भरकर तस्वीरें वायरल हैं. जिसे उनके फैन पेज ने भी री-शेयर किया है. जिस फिल्म की यहां बात हो रही है, वो है सूर्या. जिसे M. Padmakumar डायरेक्ट कर रहे हैं. जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म जोसेफ का भी डायरेक्शन किया है. फिल्म के हिंदी एडेप्शन को कमल मुकुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले गदर 2 रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर रही.

सनी देओल के साथ 33 साल छोटी एक्ट्रेस

इस वक्त X पर सनी देओल का जो वीडियो वायरल है, उसमें एक्टर एक ड्रामाटिक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं. एक घर के नीचे वो Pragya Jaiswal के साथ नजर आते हैं. जी हां फिल्म की लीडिंग लेडी वो ही हैं. जो सनी देओल के अपोजिट नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस फिल्म में एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स किरदार निभा रही हैं. जिसके किरदार में आपको कई सारे फ्लेवर देखने को मिलेंगे. इस वीडियो में वो सनी देओल के साथ ट्विनिंग करती भी नजर आईं. वहीं, दूसरे वीडियो में सनी पाजी एक्ट्रेस के साथ बाइक वाला सीक्वेंस शूट करते दिखे हैं.

दरअसल प्रज्ञा जैसवाल को इसी साल आई 100 करोड़ी डाकू महाराज में भी देखा गया था. उससे पहले अक्षय कुमार की खेल-खेल में के लिए तारीफ बटोर चुकी हैं. प्रज्ञा एक शानदार एक्ट्रेस हैं, जो दोनों ही इंडस्ट्री में तेजी से काम कर रही हैं. दरअसल गदर 2 ने काफी तगड़ा परफॉर्म किया था. ऐसे में दोबारा उन्हीं मेकर्स के साथ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में हैं. फिल्म का राजस्थान में शूट चल रहा था, जब यह वीडियो सेट से लीक हो गए. हालांकि, उनकी इस फिल्म के लिए फैन्स काफी एक्साइटेड हैं.

अपनी मां को देखकर डर जाती थीं अनुष्का शर्मा, पिता से जुड़ी है वजह

मां को देखकर क्यों डर जाती थीं अनुष्का?

अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने माता-पिता को लेकर बातचीत की थी. इस दौरान उन्होंने ये बताया था कि वो जब 11 साल की थीं उस वक्त वो अपनी मां को देखकर डर जाया करती थीं. इसके पीछे एक खास और इमोशनल वजह है, जो उनके पिता से जुड़ी हुई है.

हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी एक्टिंग से बड़ा मुकाम हासिल किया है. वो फैंस के बीच बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुई हैं. हालांकि अनुष्का खुद को एक्ट्रेस से ज्यादा सेना अधिकारी की बेटी कहने में गर्व करती हैं. गौरतलब है कि अनुष्का शर्मा के पिता अजय कुमार शर्मा सेना में रह चुके हैं. उन्होंने साल 1999 का कारगिल युद्ध भी लड़ा था, जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिको को करारी शिकस्त दी थी.अनुष्का शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के साथ ही अपनी मां आशिमा शर्मा को लेकर भी बात की थी. वहीं एक्ट्रेस ने कारगिल युद्ध का जिक्र भी किया था. उस वक्त अनुष्का काफी छोटी थीं. उनके पिता सरहद पर दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे और तब नन्ही अनुष्का अपनी मां को देखकर डर जाया करती थीं. अनुष्का को युद्ध वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था.

मां को देखकर डर जाती थीं अनुष्का

साल 2012 में अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में कारगिल युद्ध और अपने पैरेंट्स को लेकर कहा था, कारगिल एक कठिन युद्ध था. मैं उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अपनी मां को देखकर डर जाती थी. वो पूरे दिन न्यूज चैनल चालू रखती थीं और जब किसी के हताहत होने की घोषणा होती थी तो वो परेशान हो जाती थीं.

युद्ध के दौरान फोन करते थे पिता

अनुष्का ने आगे बताया था कि कारगिल युद्ध के दौरान जब उनके पिता घर फोन करते थे तो वो बस अपने स्कूल की बातें करती थीं. क्योंकि उन्हें उस वक्त ज्यादा समझ नहीं थी और वो न ये महसूस कर पाती थी कि उनके पिता युद्ध लड़ रहे हैं. अनुष्का ने आगे कहा था, मुझे ये कहने में गर्व होता है कि मैं एक एक्ट्रेस होने से भी ज्यादा एक सेना अधिकारी की बेटी हूं.

पिता के करीब हैं अनुष्का

पिता के सेना में रहने के दौरान अनुष्का की परवरिश उनकी मां ने अकेले दम पर की थी. हालांकि फिर भी अभिनेत्री अपने पिता के ज्यादा करीब हैं. अनुष्का ने इंटरव्यू के दौरान ही इस बात को स्वीकार किया था.

'लोगों का बर्ताव हमेशा...' डेब्यू फिल्म की शूटिंग के 2 दिन बाद सेट पर नहीं जाना चाहती थीं श्रद्धा कपूर

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने साल 2024 में फिल्म 'स्त्री 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था. ये फिल्म न सिर्फ उनके करियर की बल्कि बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्मों में शुमार हो गई थी. बीते 15 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहीं श्रद्धा कपूर अब तक कई बड़ी फिल्में दे चुकी हैं. लेकिन, एक्ट्रेस अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दो-तीन दिन बाद ही सेट पर नहीं जाना चाहती थीं.श्रद्धा कपूर ने अपनी फिल्म स्त्री 2 की सक्सेस के दौरान एक इंटरव्यू में अपनी डेब्यू फिल्म और करियर के शुरुआती दिनों को लेकर बात की थी. तब अभिनेत्री ने बताया था कि डेब्यू फिल्म के सेट पर वो बुरी तरह से टूट चुकी थीं. एक्ट्रेस ने कहा था कि हर किसी का बर्ताव अच्छा नहीं होता है.

मां से कहा था- मुझे वापस नहीं जाना

बता दें कि श्रद्धा कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'तीन पत्ती' से किया था. ये पिक्चर साल 2010 में रिलीज हुई थी. एक्ट्रेस ने एक बातचीत के दौरान कहा था, मुझे याद है फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए दो या तीन दिन ही हुए थे. मैं टूट चुकी थी. मैंने मां से कहा था कि मुझे वापस नहीं जाना.

लोगों का बर्ताव हमेशा अच्छा नहीं होता था

अभिनेत्री ने आगे कहा था कि उन्होंने कभी भी किसी फिल्म के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम नहीं किया था. वो सीधे अपनी पहली फिल्म के लिए सेट पर थी. श्रद्धा ने आगे कहा था, मैं उस वक्त 20 से 21 साल की थी. लोगों का बर्ताव हमेशा अच्छा नहीं होता था. अगर आप कुछ नहीं हैं तो आपसे अलग तरीके से बात होगी और अगर आप कोई खास शख्स हैं तो बात करने का तरीका बदल जाएगा. सभी को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है. लेकिन, मुझे ये सब देखकर बहुत खराब लगता था.

फ्लॉप रहा था श्रद्धा का डेब्यू

श्रद्धा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दीं हैं. लेकिन, उनका डेब्यू फ्लॉप

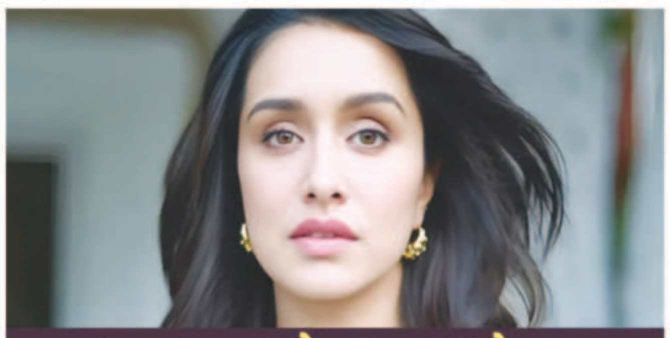

श्रद्धा कपूर को सताता था ये डर

साबित हुआ था. तीन पत्ती का डायरेक्शन लीना यादव ने किया था. इसमें अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले, आर माधवन और राइमा सेन भी लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी.

डॉक्यूबे पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट्री डर्टी एंटरटेनर्स द बिजनेस ऑफ इंडियन इरोटिका ने दिखाए परदे के पीछे का सच

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली: आईएन10 मीडिया नेटवर्क के वैश्विक डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म डॉक्यूबे ने अपनी नई और साहसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री डर्टी एंटरटेनर्स द बिजनेस ऑफ इंडियन इरोटिका रिलीज की है। हीना डीसूजा के निर्देशन और ूमरा मूवी के निर्माण में बनी यह फि ल्म भारत के भूमिगत इरोटिका उद्योग की उस हकीकत को सामने लाती है, जो अब तक परदे के पीछे रही है।

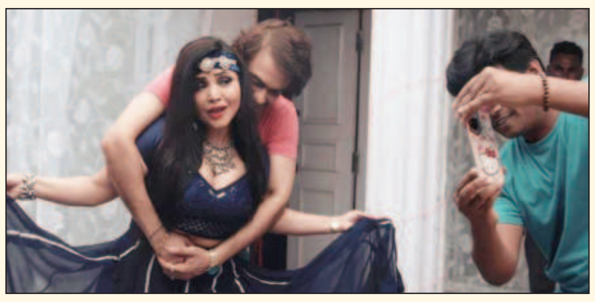

डॉक्यूमेंट्री में इस उद्योग से जुड़े कलाकारों और निमार्ताओं की निजी कहानियों के जरिए यह दिखाया गया है कि सेंसरशिप, सामाजिक कलंक और ओटीटी प्रतिबंधों के बीच यह इंडस्ट्री कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। फि ल्म में शेक्सपीयर, माया जाफर और राजसी वर्मा जैसे नामचीन कलाकारों के साक्षात्कार शामिल हैं, जो इस दुनिया की सच्चाई और संघर्ष को खुलकर सामने रखते हैं।

आईएन10 मीडिया नेटवर्क के प्रबंध निदेशक आदित्य पिट्टी ने कहा, हमारी कोशिश हमेशा से ऐसे विषयों पर काम करने की रही है, जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। डर्टी एंटरटेनर्स एक ऐसा ही प्रयास है जो बोल्ड, प्रासंगिक और वास्तविक है। मुख्य परिचालन अधिकारी समर खान ने कहा, यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इरोटिका की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि उसके आर्थिक पक्ष, कंटेंट और सेंसरशिप के जटिल रिश्ते को भी उजागर करती है। निर्माता अभिषेक गौतम ने बताया, हमने उन कलाकारों को मंच देने की कोशिश की है जो इस उद्योग में वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन कभी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाए। DocuBoy के माध्यम से यह कहानी वैश्विक दर्शकों तक पहुँचेगी। निर्देशक हीना डीसूजा के अनुसार, इस फि ल्म का मकसद इस दुनिया को इंसानियत की नजर से दिखाना था – बिना निर्णय के, सिर्फ. सच्चाई के साथ।

डर्टी एंटरटेनर्सः द बिजनेस ऑफ इंडियन इरोटिका अब DocuBoy Originals पर विशेष रूप से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, एक की मौत, तीन गंभीर

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर के चील्ह थाना क्षेत्र के चील्हझगोपीगंज मार्ग पर गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी बसही निवासी 17 वर्षीय चंदन पुत्र मैनेजर अपने साथी 20 वर्षीय चंदन पुत्र राजेंद्र के साथ बाइक से गोपीगंज की ओर से मीरजापुर आ रहा था। इसी दौरान तिलठी गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक, जिस पर मेरठ निवासी 30 वर्षीय आरिफ अली पुत्र आर्यन अली और 20 वर्षीय शादाब अली पुत्र शरीफ अली सवार थे, से आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर चेतगंज चौकी प्रभारी अरविंद गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को ट्रामा सेंटर भिजवाया। वहां उपचार के दौरान चंदन पुत्र राजेंद्र की मौत हो गई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि तीनों घायलों का उपचार ट्रामा सेंटर में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां कोहराम मच गया। थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है, तीन घायल हैं।

करवाचौथ के दिन मां ने बेटे संग खाया जहर

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा में करवाचौथ के दिन महिला ने मासूम बेटे के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने अचेतावस्था में उपचार के लिए दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सक ने मां बेटे की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया है, वहीं पर्व के दिन आत्मघाती कदम उठाने से इलाके में सनसनी फैल गई है।

दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के लवकुशनगर तहसील क्षेत्र के चितहरी गांव का है। जहां जयहिंद की पत्नी सविता (25) ने पहले अपने बेटे ऋतिक (5) को जहर खिलाया और फिर खुद भी उसका सेवन कर लिया। जिसके बाद मां बेटा दोनों अचेत हो गए।

ससुर लक्षीराम ने बताया कि बहु और नाती को अचेत देख उनके होश उड़ गए। जिसके बाद आनन फानन में बहु सविता और नाती रितिक को उपचार के लिए महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां मां बेटे की हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है।

कन्नौज में डिप्टी सीएम ने किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के खैरनगर में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्रीराम अरुण की सातवीं पुण्यतिथि पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस सभा का आयोजन श्रीराम अरुण के पुत्र और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किया। कन्नौज, फरुर्खाबाद और कानपुर देहात जिले के सभी भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष और सभी प्रमुख नेता भी इस आयोजन में मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय श्रीराम अरुण को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जिले में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें खैरनगर और मानीमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल के रूप में समर्पित करना शामिल है। ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र एचडीएफसी बैंक के सीएसआर फंड से दिए जा रहे धन से उच्चीकृत किये जा रहे हैं। साथ ही, खैरनगर में समाज कल्याण विभाग 65 लाख की लागत से एक विशाल और सभी सुविधाओं से युक्त बारात घर का निर्माण करा रहा है। आज इसका भी बटन दवाकर शिलान्यास किया गया।

शुद्ध कनौजिया भाषा में बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कन्नौज से अपने पुराने सम्बन्धों को ताजा किया और कहा कि बचपन से उनका कन्नौज आना जाना रहा है। वे बस से उतरकर तांगे पर बैठकर अपनी बुआ के घर जाया करते थे। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे किसी भी समय अपने बेटे की तरह संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का आभार भी व्यक्त किया।

78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तैयारियाँ व्यापक स्तर पर

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। निरंकारी मिशन का 78वां वार्षिक संत समागम, पूर्ववर्ती वर्षों की दिव्यता और गरिमा के अनुरूप, इस वर्ष भी 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2025 तक समालखा (हरियाणा) स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर अत्यंत भव्यता, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ आयोजित होने जा रहा है। यह दिव्य आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सान्निध्य में संपन्न होगा, जिसकी शुभ सूचना ने समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदयों में अपार हर्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया है। आत्ममंथन विषय* पर आधारित इस वर्ष का वार्षिक संत समागम अपने आप में एक अद्भुत एवं अनुपम आध्यात्मिक यात्रा है, जहां श्रद्धालु ब्रह्मज्ञान की आंतरिक ज्योति में सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए आनंद और प्रेमाभक्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस दिव्य उत्सव की तैयारियाँ अत्यंत श्रद्धा, लगन एवं निःस्वार्थ भावना से की जा रही हैं। श्रद्धालु भक्त, चाहे वे वृद्ध हों या युवा, पुरुष हों या महिलाएं,

हर पृष्ठभूमि के भक्त सेवा में पूर्ण रूप से रत हैं। प्रातः काल की प्रथम किरण से लेकर संध्या के अंतिम प्रकाश तक, हर ओर भक्ति भाव से समर्पित सेवा का अपूर्व आलोक दिखाई देता है। कोई मिट्टी के तसले ढो रहा है, कोई शामियाने गाढ़ रहा है, तो कोई सफाई, जल प्रबंधन या भोजन व्यवस्था में जुटा है। 78वें वार्षिक संत समागम की भव्यता को प्रकट करता हुआ मुख्य गेट भी आकार लेने लगा है - एक ऐसा प्रवेश-द्वार, जो प्रेम, समरसता और आत्मिक एकत्व की यात्रा का प्रतीक बनेगा। यह सब कुछ समर्पण की उस भावना का प्रमाण है, जो सतगुरु के ज्ञान से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार कहा भी गया है कि जहाँ सेवा में समर्पण जुड़ जाता है, वहीं हर क्षण उत्सव बन जाता है। सेवा भाव की गरिमा को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सेवकों के मुखमंडलों पर कोई थकान नहीं, अपितु आनंद और उल्लास की आभा झलक रही है। यह वही दिव्य आनंद है, जिसे केवल सतगुरु की छत्रछाया में रहकर, सेवा और भक्ति के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। सतगुरु माता जी भी अपने प्रवचनों में बारंबार यही प्रेरणा देती हैं कि तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र दिये दान, मन पवित्र हरि भजन सों, त्रिबिध होई कल्याण।

देश के कोने-कोने से ही नहीं, अपितु विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु भक्त इस संत समागम में सम्मिलित होने के लिए पधारते हैं। उनके स्वागत एवं सुविधाओं हेतु सभी आवश्यक प्रबंध अत्यंत सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर निरंकारी सेवादल के अनुशासित, मर्यादित एवं सुसज्जित सेवादार अपनी नीली और खाकी वर्दियों में श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें उनके निर्धारित निवास स्थलों तक ससम्मान पहुँचाने हेतु सतत तत्पर रहेंगे। निसंदेह यह समागम केवल एक साधारण आयोजन नहीं, अपितु मानवता के उत्थान और समरसता के जागरण का एक अनुपम पर्व है, जहाँ विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परिवेशों से आए श्रद्धालु भक्त वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आत्मसात करते हुए, सतगुरु की अमृतवाणी से अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हैं। इस पावन अवसर पर हर उस सज्जन, भाई व बहन का हृदय से स्वागत है, जो प्रेम, शांति, समरसता के इस दिव्य महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहती है।

दहेज की मांग पर विवाहिता को घर से निकाला

हमीरपुरः राठ कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहित को मारपीट कर घर से निकाल दिया है और ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए की मांग की थी पीड़िता ने अपने मासूम बच्चों के साथ राठ कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई राठ कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव निवासी मनोरमा पत्नी अश्विनी ने गुरुवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह पिछले वर्ष 26 फरवरी 2024 को अश्विनी के साथ हुआ था मनोरमा के अनुसार शादी के 3 महीने बाद से ही उनके पति सास और ससुर को कम दहेज लाने का ताना देने लगे उन्होंने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख और मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मायके से यह सब लाने का दावा बनाया ।

अखंड सौभाग्य के लिए वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी (काशी)में सुहागिन महिलाओं ने कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करवा चौथ पर शुक्रवार को अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा है। शाम को मां गौरी के साथ भगवान गणेशजी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद चलनी से पतिदेव का दर्शन कर पानी पीकर व्रत का समापन करेंगी। शहर में कई स्थानों पर और सामाजिक संस्थाओं में करवाचौथ का भी आयोजन किया गया है। इसके पहले भोर में व्रती महिलाओं ने सरगी निगल कर व्रत की शुरूआत की। घरों में एक दिन पहले ही साफ-सफाई के साथ पूजन सामग्री, फल, नये वस्त्र रंग बिरंगी चटक सूर्ख रंग की डिजाइनदार साड़ियां व सलवार सूट

की खरीददारी की गई। महिलाओं ने घर में महावर रचाया तो कुछ ने ब्यूटी पार्लरों का भी सहारा लिया। जगतगंज की नवविवाहिता कंचन श्रीवास्तव, संगीता चौबे ने बताया कि सासू मां की देखरेख में त्यौहार पर व्रत रखा है। उनके देखरेख में पूजा अर्चना और अन्य रस्मों को शाम को सम्पन्न करना है। व्रत रखने पर असीम शांति की अनुभूति हो रही है। व्रत में पति और अन्य परिजनों ने भी सहयोग किया। जगतगंज की ही आभा पांडेय, गीता अस्थाना ने बताया कि अखंड सुहाग की कामना को लेकर व्रत रखा है। पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद शाम को चन्द्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना है। बताया कि पिछले 10-12 सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही है।

गौरतलब हो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरूआत 09 अक्टूबर को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो गई। उदया तिथि के मान के चलते शुक्रवार को पर्व मनाया जा रहा है। पर्व पर सुहागन स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला उपवास कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। शाम को 16 श्रृंगार रचाकर व्रती महिलाएं मां गौरी पार्वती, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, दीप आदि अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ करती है।

आयुर्वेद के लाइसेंस पर एलोपैथिक उपचार, किशोर की मौत के बाद अस्पताल सील

गौतम बुद्ध नगर। थाना जारचा के प्यावली गांव में स्थित एक अस्पताल मे इलाज के दौरान एक किशोर की हुई मौत के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की जांच में अनियमितता मिलने पर गांव के निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल के पास आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाइसेंस था, जबकि वहां पर एलोपैथिक उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्यावली गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार में स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी थी कि उनका भतीजा रजत भाटी 4 अक्टूबर को गांव के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे रजत की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी डॉ रविंद्र कुमार ने इस मामले की जांच की तथा अनियमित पाए जाने पर अस्पताल को बृहस्पतिवार को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अस्पताल प्रबंधन को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जवाब अगर संतोषजनक नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डॉ रविंद्र कुमार की अगुवाई में स्वास्थ्य टीम ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि अस्पताल के पास केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाइसेंस है, लेकिन वहां एलोपैथिक दवाएं, एक्स-रे मशीन और हड्डी जोड़ने के उपकरण मौजूद थे।

निमार्णाधीन नौसेना शौर्य संग्रहालय के कार्यों की प्रगति का प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने किया स्थलीय निरीक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय नौसेना की वीरता और गौरव को समर्पित निमार्णाधीन शौर्य संग्रहालय के कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता तथा संग्रहालय की भावी उपयोगिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की। स्थलीय निरीक्षण से पहले प्रमुख सचिव ने नौसेना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था संग पर्यटन निदेशालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा, नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आकर्षण केंद्र बनेगा। यह न केवल नौसेना की गौरवशाली विरासत को दर्शाएगा, बल्कि युवाओं विशेषकर बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत करेगा।

अमृत अभिजात ने नौसेना शौर्य वाटिका के मुख्य गेट की रूपरेखा

पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव दिए। बैठक में प्रमुख सचिव को बताया गया कि इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन के संरचनात्मक कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं और शेष फिनिशिंग कार्य तेजी से किया जा रहा है। क्यूरेशन कार्य के अंतर्गत डिजिटल डिस्प्ले और थीम आधारित गैलरी की तैयारी जारी है। विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रदर्श सामग्री के चयन और डिजाइन पर कार्य किया जा रहा है। ओपन-एयर म्यूजियम के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का मसौदा तैयार किया जा चुका है। इसे संबंधित विभागों से अनुमोदन हेतु भेजा गया है। कलाकृतियों के चयन, रखरखाव और स्थापना की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। प्राथमिक रूप से चुनी गई कलाकृतियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में ळव-142 विमान और रङ-42इ हेलिकॉप्टर के सुरक्षित परिवहन एवं स्थापना से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नौसेना शौर्य संग्रहालय परिसर में डिजिटल अभिलेखागार, स्मृति उद्यान, शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र सहित कई विशेष खंड विकसित किए जाएंगे। परियोजना का मुख्य आकर्षण समुद्री संरक्षण पर आधारित थीम होगी।

फरियाद से समाधान तक नोएडा पुलिस पूरे प्रदेश में अव्वल

गौतम बुद्ध नगर। आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में सितंबर महीने में कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सितंबर महीने की रैंकिंग में इस बार जिले के सभी 27 थानों की रैंकिंग पहली रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सितंबर माह की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है।

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने बताया कि आईजीआरएस एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे सरकार की तरफ से आम नागरिकों की शिकायतो व समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायती पत्रों की त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए प्रत्येक शुक्रवार को समीक्षा की जाती है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321